● वर्ष-4
● अंक-176
रायपुर, मंगलवार
04 मार्च 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8» बजट विशेष

हर छत्तीसगढ़िया को मिला लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रू. प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने थोक में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17त्र कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है। वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3त्र की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी। छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर, गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है। आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा।

छत्तीसगढ़ बजट की बड़ी बातें

सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पेंशन फंड पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन फंड बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे। साथ ही, देश में पहली बार छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

अब हर गांव में मोबाइल टॉवर और पब्लिक बसें

- गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता। सरकार अब मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा। इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे।
- कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग कम होते हैं। अब सरकार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें।

– छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है-

- नवा रायपुर में मेडिसिटी एक ऐसा शहर जहाँ सबसे अच्छे अस्पताल होंगे।
- एजुकेशन सिटी यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी।
- राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (ह्वढ्ढस्नञ्ज) जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा।
- रायपुर-दुर्ग मेट्रो- अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके।

सुरक्षा और पर्यटन: नई योजनाएं

- NSG की तर्ज पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यह एक खास पुलिस टीम होगी, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी।
- अब राज्य में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा। इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी।
- छत्तीसगढ़ का पहला आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन रही है, जहाँ जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मज़ा मिलेगा! सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है।

गाँव-गाँव तक चमकेंगी पक्की सड़कें

- अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी। इसके लिए –
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ?845 करोड़ करोड़
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान।

शहर और गाँव दोनों होंगे स्मार्ट

- नगर पालिकाओं का विकास 750 करोड़ (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा)
- नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, 500 करोड़ का प्रावधान
- नई फायर स्टेशन्स के लिए ?44 करोड़ (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत)

बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और एडवेंचर की दुनिया

अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है। अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे।

छात्रों के लिए नया तोहफा

छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और नालंदा लाइब्रेरी खोली जाएंगी। यही नहीं, विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी। अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा।

कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम

अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी! भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है। इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार

राज्य के गरीब और नि:संतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऋञ्च सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों में स्रद्ध और ष्टञ्ज स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे

बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन

अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी! सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे।

चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम

रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। नक़ली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा क़दम है। छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है। इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी।

'आइकॉनिक डेस्टिनेशन'

छत्तीसगढ़ में पहली बार 'आइकॉनिक डेस्टिनेशन' और 'वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म' के लिए ?200 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा।

व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत

बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा। वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ा कर 1 लाख रुपए की गई है। छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट आज पेश किया। इस बजट में नौकरियां, शिक्षा समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को सदन में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार अच्छी नियत और पूरी कर्मठता के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस बार का बजट मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है।

- छत्तीसगढ़ में एक रुपये सस्ता होगा पेट्रोल।
- सरकारी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए की घोषणा।
- रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए होगा सर्वे।
- दलहन-तिलहन को MSP पर खरीदने का फैसला।
- प्रदेश में एनएसजी की तर्ज पर बनेगा एसएजी।
- सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ का होगा गठन।
- दिव्यांगों के विशेष स्कूल के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सड़क निर्माण के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।

बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी तीव्र गति - सीएम साय

रायपुर। यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी। इसमें धान के कटोरे की चमक ''कृषि अर्थव्यवस्था'' को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के दूसरे साल के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपरोक्त बातें कही। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करें, बजट में पूरा फोकस इसी पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश में बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत मिली थी। हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुन: आरंभ कराए। अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है। बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले।

इस बार बजट का थीम है ''ज्ञान के लिए गति'' यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हम इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं।

इस बजट में सरकार का विजन स्पष्ट है....

त्वरित टिप्पणी
डॉ. रविंद्र ब्रम्हे

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज पेश किए गए बजट में दो प्रमुख बातों का ध्यान रखा है. पहला राज्य को कैसे विकास की ओर ले जाया जाए और कितनी तेज गति से ले जाया जा सकता है, उसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है जो किसी भी राज्य का विकास करने के लिए जरुरी है. यदि विकास नहीं करेंगे तो टैक्स के रूप में रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले विकास होना चाहिए. बजट में किस प्रकार से नई तकनीक का उपयोग करें, कहां रोजगार बढ़ाया जा सकता उसे लेकर खास ध्यान दिया गया है. सब्सिडी उन्हें दी जा रही है जहां रोजगार बढ़ाने की संभावना है. बजट में गवर्नेंस की बात कही गई है. अनावश्यक कानून, अनावश्यक रुकावटें और लाल फीताशाही के द्वारा अवरोध पैदा किया जाता है, उसे कैसे कम किया जा सकता है इस चिंता की गई है. जीएसटी के मामलों में 10 साल पुराने लगभग 25000 केस में नए प्रावधान होने से फायदा मिलेगा. गवर्नेंस के जरिए इसका सुधार भी किया जा रहा है. इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा रही है जो बजट के प्रावधान में शामिल हैं. दूसरी ओर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी राज्य के लिए जरूरी है. सबसे ज्यादा जीडीपी इंडस्ट्री देती है, उसके बाद सर्विस सेक्टर है. इस सेक्टर के लिए लगभग 19 फीसदी की वृद्धि की गई है. इस बजट में गति की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है, गवर्नेंस की बात कही गई है. सबसे बड़ी बात बजट में है वो है सुधार की बात. उसके लिए राजकोषीय प्रबंधन किया गया है. 165000 करोड़ का यह बजट है इसमें जो राजकोषीय घाटा है वह नियंत्रित है, उसके लिए बताया गया है कि तीन प्रतिशत से कम होना चाहिए , वह 3 फीसदी से कम रखा गया है. इसी आधार पर राज्य की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है. छत्तीसगढ़ में लगातार पापुलेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 15 साल से 59 साल तक के लोग की जनसंख्या 2025 तक लगातार बढ़ रही है. महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है. युवाओं की संख्या ज्यादा है, यह यंगेस्ट स्टेट है, राज्य को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में कैसे सुविधा दी जा सकती है, इसके लिए सरकार का एक स्पष्ट विजन इस बजट में देखने को मिला है. बजट में कही गई बातों पर अमल किया जाता है तो राज्य एक नई प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा. वर्तमान में 5 साल में जीडीपी दोगुना करने की बात कही गई है. जीडीपी 2047 तक 6 गुना बढ़ाये जाने का लक्ष्य रखा गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है. पेट्रोल के दाम 1 काम किए गए हैं. कंज्यूमर उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश इस बजट में की गई है. महंगाई से उपभोक्ता परेशान है. एक हब तैयार किया जा रहा है जहां मेडिकल, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल पार्क इन सारी चीजों को वहां स्थापित करने की तैयारी है. उद्योग व्यापारी सहित सभी वर्गों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा है. महिलाओं और ग्रामीण विकास के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं. नगरों के विकास की बात कही गई है. कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित करने की बात है. इसका लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा. घाटे का बजट ही अच्छा माना जाता है, फायदे का बजट अच्छा नहीं माना जाता है . हालांकि घाटा कितना होना चाहिए, इसका देश में कानून बनाया गया है और उसके तहत ही बजट पेश किया जाता है. 3त्र से कम वित्तीय घाटा होना चाहिए तो आपका बजट अच्छा होता है।

–

तीन रात जागकर ओपी चौधरी ने लिखा 100 पेज का बजट भाषण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए एक नया इतिहास बना दिया। उन्होंने टाईप किया हुआ बजट पढ़ने की बजाए 100 पेज का स्वलिखित बजट पढ़ा। देश में अभी तक किसी वित्त मंत्री ने स्वलिखित बजट नहीं पढ़ा है। लिहाजा, सोशल मीडिया में हस्तलिखित बजट आज ट्रेंड करने लगा।

हालांकि, 100 पेज का बजट लिखना आसान नहीं था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इसके लिए लगातार तीन रात जागना पड़ा। रोज 30 से 35 पेज उन्होंने अपने हाथ से लिखा।

दिक्कत यह थी कि एकाध अक्षर या एक लाईन गड़बड़ तो फिर से उसे लिखना। इसलिए क्योंकि, बजट की कॉपी सरकारी दस्तावेज बन जाता है। सो, साथ-सुथरा भी लिखना था। घिसटौवा भी नहीं...क्योंकि, विधानसभा में कैमरे के सामने उसे पढ़ना था।

जाहिर है, ओपी हिन्दी के स्टूडेंट रहे हैं। यूपीएससी में हिन्दी सब्जेक्ट से उन्होंने आईएएस की परीक्षा क्लियर किया था। इसलिए भाषा भी अच्छी है और लिखावट भी। बजट लेखन में इसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया।

शिव की पूजा और मां का आर्शीवाद: पत्रकारों की सम्मान निधि हुई दोगुना, रायपुर प्रेस क्लब भवन के रिनोवेशन एवं विस्तार के लिए 1 करोड़ का प्रावधान...

विधासभा के लिए निकलने से पहले ओपी चौधरी ने घर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। इसके बाद मां से फोन से आर्शीवाद लिया। मां उनकी पैतृक गांव बायंग में रहती हैं। इसके बाद वे वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे।

युवा और बेरोजगारी: ओपी चौधरी ने युवाओं और बेरोजगारी को बजट के केंद्र में रखा। एनपीजी न्यूज ने फोन पर उनसे पूछा कि बजट में वह कौन सी

घोषणाएं हैं, जिससे ओपी चौधरी को सुकून मिला होगा? ओपी चौधरी ने कहा कि बजट की सारी घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं।

फिर भी मोबाइल टावर योजना और नर्सिंग कालेजों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 करना उन्हें अच्छा लगा। राज्य बनने के 24 साल में 8 नर्सिंग कॉलेज खुले थे, इस बार एक साथ 12 खोलने का प्रावधानप किया गया है। नर्सिंग की इस समय काफी डिमांड है। नर्सिंग करने के बाद कम-से-कम कोई रोजगार के लिए भटकेगा नहीं।

रोजगार पर फोकस: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट में इंडस्ट्री का बजट बढ़ाकर दुगुना किया गया है। इस बार छूट को बेरोजगारी से जोड़ा गया है। जो इंडस्ट्री जितना अधिक युवाओं को नौकरी देगा, उस हिसाब से उसे छूट मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि उद्योगों में अधिक-से-अधिक रोजगार का सृजन हो, ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले।

होम स्टे पॉलिसी: ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार होम स्टे पॉलिसी बनाने जा रही है। इस पॉलिसी पर अगर ढंग से क्रियान्वयन हो गया तो गांवों की दशा और दिशा बदल जाएगी। कई देशों में होम स्टे पॉलिसी से वहां की अर्थव्यवस्था बदल गई।छत्तीसगढ़ की होम स्टे पॉलिसी के लिए विषय विशेषज्ञों से बात कर ली गई है। गांवों के एक व्यक्ति को छह होम स्टे पॉलिसी बनाने का अवसर मिलेगा। इसे बनाने के लिए राज्य सरकार 50 परसेंट सब्सिडी देगी। सरकार ग्रामीणों को बैंक से लोन दिलाएगी और लोन का इंटरेस्ट भी सब्सिडछी के तौर पर देगी। इससे खासकर, बस्तर के लोगों को काफी फायदा होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलमुक्त हो रहा है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता किसी से छिपी नहीं है। बस्तर में जल्द ही बड़ी संख्या में सैलानियों की आवाजाही प्रारंभ हो जाएगी। होम स्टे से बस्तर के गांवों की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी।

मोस्ट वॉन्टेड नक्सली का सरेंडरः आठ लाख के इनामी ने किया आत्मसमर्पण

कई बड़ी घटनाओं में था शामिल

जगदलपुर। बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने अपने परिवार समेत आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है आत्मसमर्पण करने वाले डीवीसीएम कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। अचानक से उसके द्वारा समर्पण कर देने से नक्सलियों को काफी बड़ा झटका लगा है।

बता दें कि बीजापुर गंगालूर एरिया कमेटी का मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर डीवीसीएम दिनेश मोडियम समर्पण करने पत्नी और बच्ची को भी साथ लेकर पुलिस के पास पहुंचा था। नक्सलियों की गंगालूर एरिया कमेटी का सबसे खास होने के साथ ही दुर्दांत नक्सली दिनेश बताया जा रहा है।

दिनेश के अचानक से संगठन को छोड़ने से नक्सलियों के संगठन को बड़ा झटका लगा है। दिनेश नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर आतंक को छोड़ दिया। गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सली डीव्हीसीएम दिनेश मोडियम ने सोमवार को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

दिनेश पर 8 लाख का इनाम घोषित था और वह कइयों हत्याओं को अंजाम दे चुका था। जिसके चलते दिनेश का नाम टॉप लिस्ट में चल रहा था। दिनेश मोडियम लंबे समय से पुलिस के निशाने पर था। वह कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहा है। जिसमें सुरक्षा बलों और निर्दोष ग्रामीणों की हत्याएं शामिल होने की बात सामने आई थी। पुलिस लंबे समय से दिनेश की तलाश कर रही थी।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा चलाए जा रहे लगातार ऑपरेशनों और बढ़ते दबाव के चलते दिनेश ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया।

विधायक दलेश्वर अब साहू समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल

■ साहू समाज ने लिया कठोर निर्णय

राजनांदगांव। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में साहू समाज के उम्मीदवारों के खिलाफ गैर साहू समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने की साजिश के आरोप के तहत डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू के खिलाफ साहू समाज ने मोर्चा खोलते हुए उन्हें किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने का कठोर निर्णय लिया गया है ताकि समाज के खिलाफ खड़े होने वाले विरोधियों को कड़ा संदेश मिले।

रविवार को जिला साहू समाज की बैठक आहूत की गई। बैठक में समाज के अध्यक्ष भागवत साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने पूजा-अर्चना कर बैठक की शुरूआत की। जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में चार विषयों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सामाजिक पदाधिकारियों के विरूद्ध डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू द्वारा उनके चुनाव को प्रभावित करने का कार्य किया। विधायक के उक्त कृत्य के लिए जिला साहू समाज द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जिला साहू संघ के सामाजिक कार्यक्रमों, सामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही कर्मा जयंती 25 मार्च को जिला साहू संघ में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। उक्त तिथि को किसी भी अन्य ग्राम परिक्षेत्र तहसील में कर्मा जयंती का आयोजन नहीं किया जाएगा।

उसी तरह तहसील परिक्षेत्र में कर्मा जयंती होने पर अन्य आयोजन नहीं किया जाएगा। मां भानेश्वरी जयंती आगामी 9 मई को मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। ग्राम परिक्षेत्र तहसील का सामाजिक चुनाव आगामी 15 से 30 अप्रैल तक होगी। बैठक में सामाजिक पदाधिकारीगण शामिल थे।

रईसजादे का पुलिस ने निकाला जुलूस

■ शराबी ने गाड़ी से कई ठेलों को मारी थी टक्कर

कोरबा। कोरबा में रविवार रात एक वाहन ने बाजार में तांडव मचाया। काले रंग की इस गाड़ी ने टीपी नगर जैसे रिहायशी इलाके में कई ठेलों को अपनी चपेट में लिया इस दौरान वाहन चालक ने अपनी गति धीमी नहीं की वो एक के बाद एक सामने में जो आया उसे अपनी गाड़ी से ठोकर मारता गया और फरार हो गया। गैरजिम्मेदाराना ड्राइविंग के कारण कई लोग घायल हुए इसी दौरान एक स्थानीय ने वाहन का वीडियो बना लिया जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी को कुसमुंडा से दबोचा।

टीपी नगर क्षेत्र में इंडियन कॉफी हाउस से प्रेस काम्प्लेक्स की तरफ जाने वाली सड़क पर रविवार रात करीब साढ़े 9 बजे कहर बरपाने वाले आरोपी की पहचान कोयला कारोबारी राकेश यादव के तौर पर हुई है। आरोपी गेवरा निवासी है जो अपनी जीप छ्ग 12 ब्छ 5048 को शराब के नशे में अकेले ड्राइव कर रहा था इस दौरान उसने सड़क पर लगने वाले ठेलों को क्षतिग्रस्त किया।

सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना ने बताया कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलने वाला युवक राकेश यादव को पकड़ा गया है। उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना ने कहा बीती रात वह शराब के नशे में था, अब तक की पूछताछ में उसने अकेले ही शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की बात कबूली है। जिससे लगभग 40000 रुपए का नुकसान हुआ है। जुर्माना की राशि का आकलन हमने किया है। जिसे आरोपी को कोर्ट में पटाना होगा, मामले में और भी जांच की जा रही है।

आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई थी। वीडियो के आधार पर आरोपी को कुसमुंडा से गिरफ्तार किया। सोमवार दोपहर पुलिस ने इस आरोपी का उसी जगह पर सार्वजनिक जुलूस निकाला, जहां उसने उत्पात मचाया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को हथकड़ी से बांधा और जुलूस निकालते हुए थाने ले गई।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मिलुपारा में सफल आयोजन

अदाणी फाउंडेशन की चलित विज्ञान प्रयोगशाला ने बढ़ाया आकर्षण

रायगढ़। अदाणी फाउंडेशन के तत्वावधान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिलुपारा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। तमनार प्रखंड के 18 शासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चलित विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से लगभग 1500 विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम में लगभग 200 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से विषय को गहराई से समझने का अवसर प्राप्त किया। इस दौरान 11वीं कक्षा के छात्र भोला सिदार और छात्रा ईशा नागवंशी ने नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. सी. वी. रमन की खोज 'रमन प्रभाव' और फोटोन सिद्धांत के बारे में जानकारी साझा की।

इस अवसर पर अदाणी फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई छत्तीसगढ़ की पहली चलित विज्ञान प्रयोगशाला भी आकर्षण का केंद्र बनी। इस प्रयोगशाला के प्रशिक्षकों ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन किया, जिसमें मौसम परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की धूरी, दिन और रात के बदलाव, प्रकाश परावर्तन प्रक्रिया आदि को मॉडल्स के माध्यम से समझाया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि मिलुपारा सरपंच उद्धव भगत और विशिष्ट अतिथि विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष भिखलाल नायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गारे पेलमा द्वितीय के जीएम (एचआर) श्रीनिवास रेड्डी, पर्यावरण विभाग के सुजीत तिवारी, प्रौद्योगिकी विभाग के राम दयाल पटेल और सीएसआर विभाग के अन्य सदस्य भी शामिल हुए।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। यह दिन भारतीय वैज्ञानिक डॉ. सी. वी. रमन की महान खोज 'रमन प्रभाव' की स्मृति में समर्पित है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

अदाणी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका उन्नयन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। तमनार प्रखंड के 18 शासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चलित विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से लगभग 1500 विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विज्ञान को समझने और उसे दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की स्थानीय प्रशासन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सराहना की। अदाणी फाउंडेशन और अगस्त्य फाउंडेशन के इस संयुक्त प्रयास से ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा तक पहुंच मिल रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास और वैज्ञानिक सोच विकसित हो रही है। अदाणी समूह, अदाणी फाउंडेशन के माध्यम से रायगढ़ जिले के तमनार और पुसौर प्रखंड में सीएसआर की विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहा है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका उन्नयन और ढांचागत विकास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इस पहल से 100 से अधिक गांवों के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस आयोजन ने न केवल विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाई, बल्कि प्रयोगों और मॉडल्स के माध्यम से उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान किया। अदाणी फाउंडेशन भविष्य में भी

विदेशी नागरिकों से बिटकॉइन में चलता था लेन-देन, 4 म्यूल अकाउंट होल्डर्स गिरफ्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। रायबर सेल और पेंड्रा-गौरेला थाना की संयुक्त टीम ने सायबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार म्यूल अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया है। कमीशन की लालच में ये आरोपी साइबर ठगों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड और चेकबुक देते थे। आरोपियों के खाते में कई राज्यों में हुई साइबर ठगी से जुड़ी लगभग 50 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं।

14 सी के राष्ट्रीय पोर्टल SAMANVAYA से जीपीएम पुलिस को सायबर ठगी में उपयोग होने वाले खातों की जानकारी मिली। बिलासपुर रेंज आईजी डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन और एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन में साइबर सेल और थाना पेंड्रा-गौरेला की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस की टीम ने इन संदिग्ध बैंक खातों की जांच की और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी की।

म्यूल अकाउंट मामले में पुलिस की जांच में कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के अन्य राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों से संबंध थे और ये गिरोह विदेशी नागरिकों के साथ बिटकॉइन के माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में भी शामिल थे। इन आरोपियों के खातों में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हुई साइबर ठगी से जुड़ी लगभग 50 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा, आरोपियों ने क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी कमीशन का लालच देकर दो दर्जन से अधिक बैंक खाते ठग गिरोहों तक पहुंचाए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इन आरोपियों के कुछ विदेशी नागरिकों के साथ भी संबंध थे और ये अवैध रूप से बिटकॉइन के माध्यम से लेन-देन कर रहे थे। इनके असम और गोवा में सक्रिय बड़े मनी म्यूल नेटवर्क से जुड़े होने के प्रमाण भी मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं, जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है। आने वाले समय में एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। **गिरफ्तार आरोपी-** आशीष रजक (ज्योतिपुर, गौरेला), अभिषेक शुक्ला (गौरेला), करण कुमार साहू (पेंड्रा), संतोष साहू (पेंड्रा)। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(4), 314, 61(1(2)) और 112 के तहत संगठित अपराध, ठगी से अर्जित संपत्ति के दुरुपयोग और साइबर अपराध की अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नशीली दवाओं के साथ सप्लायर व फार्मेसी संचालक गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने नशीली सिरप और टैबलेट के साथ सप्लायर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह भिलाई के अपने गुर्गों को यह बेचने के लिए जा रहा था। पूछताछ के बाद देव भक्त फार्मेसी के संचालक अजय देवांगन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जप्त नशीली सिरप और टैबलेट की कीमत लगभग 15 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने फार्मेसी के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए खाद्य और औषधि विभाग को पत्र लिखा है। दुर्ग पुलिस नशेड़ियों के अलावा जेल से रिहा हुए नशे के कारोबारियों पर भी विशेष नजर रख रही है, इसी बीच दुर्ग पुलिस को जानकारी मिली की नितेश सिंह नामक युवक दुर्ग से नशीली दवाई अवैध रूप से परिवहन कर भिलाई ले जा रहा है, जिसको वह अपने तमाम गुर्गों को बेचने के लिए सप्लाई करेगा। इसी बीच नितेश सिंह को रास्ते में रोककर उससे पूछताछ की गई और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे के टैबलेट और सिरप बरामद किया गया जिसकी कीमत 15 हजार रुपए से अधिक है को जप्त किया।

चंदन नगर ने हरिहरपुर को दी मात, 4-0 से हासिल की जीत

उदयपुर। हरिहरपुर और चंदन नगर के बीच शनिवार को खेले गए पीसीबी ट्रॉफी रात्रिकालीन फुटबॉल टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल मुकाबले में चंदन नगर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 4-0 से एकतरफा जीत दर्ज की। चंदन नगर की टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल, अद्भुत टीम वर्क और रणनीतिक खेल से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं हरिहरपुर की टीम ने चंदन नगर के कुशल क्षेत्र रक्षण के आगे घुटने टेक दिए और अंत तक एक गोल भी नहीं दाग सके। चंदन नगर की ओर से जर्सी नं। 1- आईबरन सिंह मरकाम, जर्सी नं. 5- नीलेश मरकाम, जर्सी नं. 15- बलजीत कमरो और जर्सी नं. 3- कृष्णा जगत ने एक-एक गोल दागकर टीम को शानदार जीत दिलाई। पुरस्कार वितरण समारोह में सबसे पहले मुख्य अतिथियों द्वारा पीसीबी ट्रॉफी उपविजेता टीम हरिहरपुर को 21000 का नगद पुरस्कार और उपविजेता पीसीबी कप प्रदान किया गया। अंत में पीसीबी ट्रॉफी की विजेता टीम, चंदन नगर को 31000 का नगद पुरस्कार और पीसीबी विजेता कप से सम्मानित किया गया।

भर-भराकर गिरी चार दुकानें इलाके में मची अफरा-तफरी

कोरबा। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। करीब चार दशक पहले साडा के समय अल्का कॉम्प्लेक्स में बनी चार दुकानें अचानक भर-भराकर गिर गई। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कई दुकानदार बाल बाल बच गए। इस हादसे में किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है, लेकिन दुर्घटना से कारोबारियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दुकानदारों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर निगम नाली का निर्माण करा रहा है, जिसके कारण यह हादसा हो गया। इस हादसे के बाद घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है।

महासमुंद जिला आगामी आदेश तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

महासमुंद। महासमुन्द जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (कमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जिले को आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत महासमुन्द जिले में आगामी आदेश तक सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल व्यवस्था, पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय/अर्द्धशासकीय / नगरीय निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकारी सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमत प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

रास्ते के विवाद में युवक की पत्थर, लाठी और रॉड से हमला

बिलासपुर। घर के सामने निस्तारी रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के सदस्यों ने पड़ोसी युवक पर पत्थर, लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना रविवार को बिल्हा थाना क्षेत्र के उड़गन गांव में हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार, उड़गन निवासी खेमचंद बंजारे के घर के ठीक बगल में वकील मुकेश अंचल और कोर्ट में कार्यरत उसके बड़े भाई लक्ष्मण अंचल का मकान है। खेमचंद और मुकेश के बीच निस्तारी रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। उस रास्ते से दोनों परिवार के लोगों का आना-जाना होता है। बीते 1 मार्च की रात मुकेश अंचल के पिता श्याम अंचल ने उसी रास्ते में पत्थर गाड़ दिया। जिसे रात में ही किसी ने उखाड़ दिया। इस बात को लेकर मुकेश अंचल के पिता श्याम अंचल गाली गलौच करने लगा, जिसे सुनकर खेमचंद बंजारे घर से निकला और बोला कि मैंने पत्थर को उखाड़ा है।

तालपुरी में आर्टिस्ट ने बिखेरा जादू, बाउंड्री वॉल पर खूबसूरत पेंटिंग से बढ़ाई खूबसूरती

दुर्ग। भिलाई के रिसाली नगर पालिका क्षेत्र में स्थित तालपुरी बी ब्लॉक में एक अच्छी पहल देखने को मिली है। यहां स्थानीय निवासियों की सुबह अब खुशनुमा हो गई है। लोग पहले मार्निंग वॉक में जाते हुए क्षेत्र की बाउंड्रीवॉल में लगे गोबर और उसकी बदबू से परेशान होते थे। लेकिन अब उन्हीं दिवालों पर बन रही रंग-बिरंगी खूबसूरत चित्रकारी लोगों का मन मोह रही है।

तालपुरी बी ब्लॉक की चारदीवारी पर अब सुंदर चित्रकारी दिखाई दे रही है। इस काम में आठ आर्टिस्ट लगे हुए हैं। फिलहाल, ये लगभग तीन सौ मीटर लंबी चारदीवारी पर चित्र उकेर रहे हैं। बाद में इसके अन्य हिस्से पर चित्रकारी की जाएगी। चित्रकारी का काम पूरा होने के बाद इस पर लाइटिंग भी करने की तैयारी है। दीवारों पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और विरासत को दर्शाने के साथ-साथ जल संरक्षण और पेड़ों को बचाने का संदेश भी दिया गया है।

तालपुरी बी ब्लॉक की दीवारों पर कमल, बतख, फूलदार पौधे, हिरण, पक्षी, तितली, मोर, ऊंट तथा मॉडर्न आर्ट की बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है। बच्चे इस सुंदर दीवार के चारों तरफ इकट्ठे होकर उकेरी गई तस्वीरों को निहारते हुए अपना खेलकूद और साइकल चलाते दिख रहे हैं।

तालपुरी बी ब्लॉक के निवासी यहां बाउंड्रीवॉल में लगे गोबर और उसकी बदबू से परेशान थे। पंथी चौक के पास तालपुरी बी ब्लॉक के मेनगेट तक की चारदीवारी के आसपास गोबर के ढेर के उठाव के लिए पिछले पांच सालों से मांग की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। ऑर्किड मैदान में हाई मास्ट लाइट के उद्‌घाटन के अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने गोबर की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया था।

पार्षद सविता ढवस ने कहा सौंदर्यीकरण के लिए विधायक को धन्यवाद दिया हूं। यह पहल स्वच्छता की ओर एक कदम है। वार्ड का सौंदर्यीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उद्यानों का रखाव, सफाई व बुनियादी जरूरतें हमारी प्राथमिकताओं में है। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए हाल ही में कालोनी के पहुंच मार्ग पर ब्रेकर भी बनाए गए हैं, जिससे यातायात सुगम हो गया है।

विधायक और पार्षद सविता ढवस की पहल से क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अब इस दीवार को देखकर लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गोबर से आने वाली बदबू से उन्हें राहत मिल गई है।

तालपुरी की चहारदीवारी की रौनक खूबसूरत चित्रकारी से फिर लौट गई है। गोबर की वजह से चारदीवारी पर बने छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति की झलक दिखाने वाले भित्ति चित्र लुप्त हो गए थे। अब इस दीवार पर रंग रोगन से भित्ति चित्र की रौनक फिर से लौट आई है। चारदीवारी का कायाकल्प होने से पहले यह गोबर से सनी हुई थी।

राजनांदगांव नगर निगम में सभापति कौन?

■ सांसद व पर्यवेक्षक रूप कुमारी चौधरी ने दावेदारों से की बात

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। राजनांदगांव नगर निगम में भी भाजपा की जीत हुई है। बीजेपी के मधुसूदन यादव नवनिर्वाचित महापौर बने हैं। अब नगर निगम में सभापति पद को लेकर भी एक लंबी लिस्ट सामने आई है। जिसके बाद भाजपा ने अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

राजनांदगांव नगर निगम में सभापति के चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूप कुमारी चौधरी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। रविवार को राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभापति चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद व पर्यवेक्षक रूप कुमारी चौधरी भी शामिल हुई। बैठक में चौधरी ने अध्यक्ष के दावेदारों से एक एक कर चर्चा की।

सभापति के दावेदारों से बात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। भाजपा के पार्षद भी बड़ी संख्या में जीतकर आए है। राजनांदगांव में 39 भाजपा पार्षद जीत कर आए हैं। आने वाले समय में सभापति का चुनाव होना है, इसके लिए वन टू वन सभी से बातचीत कर निर्णय लिया जा रहा है। आने वाले समय में सभापति किसे बनाएंगे इसे लेकर सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित भारत कि दिशा में आगे ले जाने वाला एक सशक्त दस्तावेज - जितेन्द्र

रायपुर। कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोषी ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी ने प्रदेश के बजट 2025 पेश किया गया। जिसकी मुख्य झलकियां निम्नानुसार छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कामॅर्स को रियायत दर पर भूमि उपलब्ध का प्रावधान किया गया। प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय किसानों और उद्यमियों के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि यह विकासशील नहीं, बल्कि विकसित बजट है, जो राज्य के व्यापारिक समुदाय, स्टार्टअप्स, डैडम् और किसानों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता देने के फैसले से राज्य का व्यापारिक परिदृश्य और अधिक सशक्त होगा। इससे प्रदेश में नवाचार, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ई-वे बिल पर दी गई छूट का स्वागत करते है।

खून से लथपथ युवक को बीएसएफ जवानों ने सीपीआर देकर बचाई जान

रायपुर। नया रायपुर में तेज रफ्तार के चलते

एक बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गया। बाइक इतनी स्पीड में थी कि वह अनियंत्रित होकर सामने डिवाइडर में जा घुसी। इस हादसे में युवक बुरी तरह घायल हो गया। युवक सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं हादसे के बाद घटना स्थल से गुजर रहे बीएसएफ के जवानों ने जब युवक को खून से लथपथ और बेहोश पड़े देखा, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए प्राथमिक उपाय कर उसकी जान बचाई। बीएसएफ के अफसर और जवानों ने घायल को सीपीआर दिया, सिर से बह रहे खून को रोकने के लिए कपड़ा बांधा और राखी पुलिस को सूचित किया। वहीं घटना की सूचना पर एंबुलेंस देर से पहुंची। इससे पहले ही बीएसएफ ने सड़क से गुजरते निजी अस्पताल के एंबुलेंस को रोककर घायल को अस्पताल राखी उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस दुर्घटना में घायल की मदद कर बीएसएफ ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है बल्कि मानवता की मिसाल भी पेश की है।

केपीएस की बस गिरी नाली में, कोई हताहत नहीं

रायपुर। विधानसभा रोड में कृष्णा पब्लिक

स्कूल की तेज रफ्तार बस डिवाइडर, पेड़ और बिजली खम्बा को तोड़ते हुए नाली में जा पलटी। गनीमत यह रही कि बस स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद से बस चालक और कंडक्टर फरार हो गए है। घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बस को नाली से निकलवाया और उसे जप्त कर लिया।

50 साल बाद नक्सलियों के गढ़ पामेड़ क्षेत्र में शुरू हुई बस सेवा

रायपुर। बीजापुर जिले का एक ऐसा इलाका जो कभी नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी, वह इलाका अब सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और जवानों की मेहनत के बलबूते विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जहां कभी बमुश्किल दुपहिया वाहन नजर आते थे अब उस इलाके में 50 साल के बाद यात्री बस की सेवा शुरू कर दी गई। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर बसा उसूर ब्लॉक के पामेड़ समेत उस इलाके के 7 ग्राम पंचायतों सहित पूरे इलाके में बस की सुविधा मिल रही है। यहां पिछले 4 महीने के अंदर विकास कार्यों ने ऐसी गति पकड़ी अब इस इलाके में सड़क और कैंप के साथ ही मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया है, तो वहीं सबसे बड़ी सौगात इस इलाके के ग्रामीणों के लिए यात्री बस की सेवा है। इस बस के संचालन के चलते अब उन इलाकों के ग्रामीणों को तेलंगाना से होते हुए अपने गांव जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ रही है बल्कि बीजपुर से सीधे पामेड़ पहुंच रहे हैं। नियद नेल्लानार के तहत पामेड़ इलाके के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी: इस मामले में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा की माने तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार के तहत उन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्यों को गति प्रदान किया जाएगा। 50 सालों तक जिन सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे थे वह सारी सुविधा उन तक पहुंचाई जाएगी। पामेड़ इलाके के ग्रामीणों के लिए बहुत तेजी से आधार कार्ड राशन कार्ड के अलावा राशन दुकान भी गांव में संचालित की जा रही है। दरअसल पामेड़ वह इलाका है जहां पदस्थ जवानों के लिए कभी वेतन से लेकर अखबार तक हेलीकॉप्टर से भेजा जाता था परंतु अब सड़क बनने और बस सेवा के शुरू हो जाने से जवानों का यह कठिन सफर खत्म हो चुका है।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री का भगवान श्रीराम को दंडवत प्रणाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर पहुंचे। मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। बजट जारी होने से पहले रविवार को वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला होगा। विकसित राष्ट्र, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट होगा। GYAN का अगला स्टेप कल पेश होगा। यह बजट सभी वर्गों के लिए रहेगा। प्रेसवार्ता में मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार को लगभग सवा साल हो गया है। 3 मार्च को साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला होगा। पिछली बार की तुलना में इस बार का बजट बड़ा होगा।

वित्त मंत्री ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री साय की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साय भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह अटल जी की जन्मशताब्दी का वर्ष भी है, ऐसे में बजट विकासोन्मुखी होगा।

सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि किसानों को बोनस दिया

गया, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई और कई अन्य योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गईं। इस बार का बजट पिछले साल के बजट का अगला चरण होगा और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।

जानें पिछले बार के बजट की खासियत

वित्त मंत्री चौधरी के पिछले पेश किए गए बजट में महिलाओं की चार दर्जन योजनाओं को कम कर 10 कर दिया गया, वहीं 22 शहरों में नालंदा जैसी लाइब्रेरी खोलने का ऐलान किया गया था।

आदिवासी भाषा विकास परिषद बनाने की घोषणा भी बजट के दौरान की थी, जवानों को स्पाइक रेजीमेंट बूट देने का एलान भी बजट में किया गया था।

ग्राम पंचायत महिला सदन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन योजना और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट बनाए जाने की घोषणा भी बजट में की गई थी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ओपी चौधरी के पिछले बजट को बिना किसी नए कर प्रावधान और मौजूदा करों के बिना वृद्धि के राजस्व बढ़ाने वाला बजट बताया था। साय ने कहा था कि यह बजट सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है।

चौधरी ने की 'मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना' की घोषणा

छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर किया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 'गति' मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोल रहे हैं। इस बीच राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को Viability Gap Funding (VGF) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू हो सके इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।

मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि डीएमएफ फंड से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। सरकार 250 करोड़ रुपये की लागत से दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी।

जनता तो छोड़िए, भाजपा के लोगों को समझ नहीं आया होगा बजटः भूपेश

छत्तीसगढ़ विधानसभा में साय सरकार ने आज 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए का 25वां बजट पेश किया किया। जिसमें विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों के लिए घोषणा की गई है। बजट को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रया सामने आई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के लंबे बजट भाषण को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सिंगल माइक पॉडकास्ट बताया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे छत्तीसगढ़ के विनाश का बजट है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर साय सरकार के नए बजट को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि ये था क्या, ये बजट भाषण था या गणतंत्र दिवस का भाषण था या किसी कवि सम्मेलन की भूमिका थी? ये था क्या? ये जनता तो छोड़िए, भाजपा के लोगों को खुद समझ नहीं आया होगा।

उन्होंने कहा कि न जनता के लिए कोई राहत, न किसान, युवा, महिला के लिए कोई घोषणा। बेहद निराशाजनक है, सिंगल माइक पॉडकास्ट समाप्त हुआ।

छत्तीसगढ़ के बजट 2025-26 को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की भी प्रतिक्रया सामने आ गई है। उन्होंने सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ के विनाश का बजट बताया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए है। यह बजट कोरी कल्पना है। इस बजट में न तो कोई नीति है और न कोई विजन। पिछले बजट का एक भी पैसा गांव ओर शहरों तक नहीं पहुंचा है। यह बजट पूरी तरीके से दिशाहीन और विनाशी बजट।

कोयला घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को दी अंतरिम जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं बाकी आरोपी अब भी जेल में बंद हैं।

बता दें, ईडी की जांच रिपोर्ट और आरोपों के आधार पर एसीबी ने कोयला घोटाला मामले की जांच कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार किया था। एसीबी ने कोल घोटाला मामले में तीनों के अलावा दीपेश टॉक, राहुल कुमार सिंह,शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नायक, रोशन कुमार सिंह,

शेख मोइनुद्दीन कुरैशी को भी गिरफ्तार किया था।

जानिए क्या है कोयला घोटाला मामला

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था। ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके। वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसपर ईडी के अनुसार निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया का हाथ था।

ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी ने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था। व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे। इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से झटका

■ निजी स्कूल अपने हिसाब से लेंगे 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से झटका लगा है। विभाग के आदेश को दरकिनार करते हुए पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को अलग कर दिया है। हाई कोर्ट जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने यह फैसला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ अन्य दो याचिकाओं पर दिया है।

वक़ील शरद मिश्रा ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में पांचवी एवं आठवीं की परीक्षाएं नहीं लेगा। हमेशा की तरह निजी स्कूल ही परीक्षा आयोजित करेंगे। इसके अलावा जो निजी स्कूल केंद्रीयकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे शामिल हो सकते हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षा लेने का शिक्षा विभाग का आदेश के खिलाफ निजी स्कूल के साथ अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मामले में निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि उन्होंने पहले ही शिक्षा विभाग को लिखकर दिया था कि वो सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब तक इन कक्षाओं के होम एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन सत्र के आखिर में पांचवीं और आठवीं की परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बता दें कि 2010-11 में कक्षा पांचवी, आठवीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त किया गया था। लेकिन बोर्ड परीक्षा बंद करने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर को देखते हुए फिर से केंद्रीयकृत परीक्षा लेने का फैसला लिया गया था।

रायपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन ईडी दफ्तर घेराव से पहले राजीव गांधी चौक पर जुटे हजारों कार्यकर्ता

■ भारी पुलिस बल तैनात

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी रायपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को राजनीतिक दुर्भावना से निशाना बना रही है। इसी के विरोध में आज, 3 मार्च (सोमवार) को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित ईडी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया है।

दरअसल, ईडी ने कांग्रेस के सुकमा जिला कार्यालय के निर्माण से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इस संबंध में कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां उनसे लगभग 9 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

ईडी दफ्तर घेरने से पहले कांग्रेस ने राजीव गांधी चौक पर एक विशाल सभा आयोजित की, जिसमें हजारों कार्यकर्ता जुटे। सभा में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलावा महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, और उन्होंने केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक, इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल होंगे।

कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि वह ईडी और केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ लगातार संघर्ष करेगी और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर रमन सिंह ने अजय चंद्राकर को टोका

कहा- हाईजैक नहीं करना है किसी का प्रश्न

रायपुर। विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान अजीब सी स्थिति बन गई, जब भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले प्रश्न करते हुए बैठ गए, क्योंकि भाजपा विधायक अजय चंद्राकर प्रश्न पूछने लग गए थे। इस पर स्पीकर डॉ। रमन सिंह ने भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को टोकते हुए कहा कि किसी का प्रश्न हाईजैक नहीं करना है।

दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान पूर्व खाद्य मंत्री और भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने रसायनिक खाद और बीज के आवंटन का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि आवंटन पहले निजी क्षेत्र को हो जाता है फिर किसानों को होता है। इसके लिए नीति बनायी जाएगी क्या? मेरे पास आंकड़ा है कि किसानों से ज्यादा निजी क्षेत्र को आवंटन दिया गया है।

इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 60 फीसदी अपने सोसाइटी के ज़रिए किसानों को देते हैं और 40 फ़ीसदी निजी क्षेत्र को देते हैं। सभी विद्वानों से बात कर इस मामले में जो बेहतर हो सकेगा उसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे।

पन्नुलाल मोहले ने गुणवत्ताहीन बीज वितरण का फिर प्रश्न करना चाहा, जिसपर आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको प्रश्न करना था तो बैठ क्यों गए। इस पर पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि अजय चंद्राकर पूछने लगे थे। अजय चंद्राकर ने कहा की आसंदी की अनुमति से प्रश्न किया हूँ। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- किसी का प्रश्न हाईजैक नहीं करना है।

इसके बाद पन्नुलाल मोहले ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि गुणवत्ताहीन बीज का वितरण मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ। क्या कार्रवाई हुई? कृषि मंत्री ने बताया कि हम बीज के बदले बीज भी देंगे। जाँच करवा लेंगे और कार्रवाई करेंगे। जो दोषी है उन पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी खाद-बीज वितरण में समस्या है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा नदी नालों में केमिकल वाटर छोड़ने का मुद्दा

■ मंत्री बोले चेतावनी के बाद भी नहीं माने तो होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दुर्ग भिलाई के उद्योगों का गंदा पानी नालों के जरिए नदी में मिलाने का मामला गूंजा।अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने विधानसभा में सवाल पूछा कि दुर्ग और भिलाई के उद्योगों का पानी शिवनाथ नदी में मिलाया जा रहा है।इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे।

इस प्रश्न के जवाब में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि उद्योगों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि वो सीधे किसी नदी में अपने गंदा पानी नहीं डाल सकते।इसके लिए उन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को रिसाइकिल करके नदी या नालों के जरिए निकासी करनी होगी।अब तक इस बारे में किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है।यदि भविष्य में शिकायत मिलती है तो ऐसे उद्योगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

कितने केमिकल प्लांट पर कार्रवाई हुई = इसके बाद विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने पूछा कि वर्ष 2024 में केमिकल बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थी।उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

इस सवाल के जवाब में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि साल 2024 में केमिकल बनाने वाली कंपनियों के 27 कंपनियों की जांच की गई थी। जिन पर कार्रवाई की गई है।यदि ये नाम चाहेंगे तो नाम दे दिए जाएंगे।

भूपेश बघेल ने दूषित जल का मुद्दा उठाया = इस प्रश्न का जवाब देने के बाद पाटन विधायक भूपेश बघेल ने भी नदियों में पानी छोड़ने के मुद्दे को उठाया।उन्होंने कोर्सेवाड़ा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उद्योगों का गंदा पानी शिवनाथ और खारुन नदी में छोड़ा जाता है। मेरे निवास स्थान से

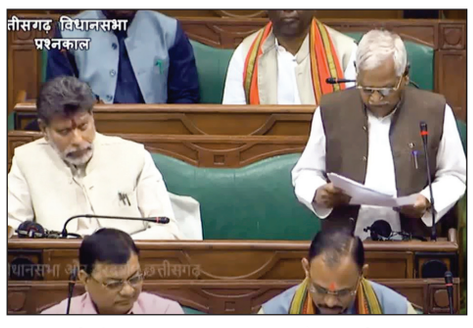

1 किलोमीटर दूर एक नाला है।जिसमें उद्योगों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके जद में कई गांव आते हैं। उसमें ये स्थिति है कि हथखोज से लेकर दादर, पथर्रा,नंदौली से होकर गुजरता है। नाले में सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ पानी छोड़ा जाता है। आज स्थिति ये है कि नाले में एक भी जलचर प्राणी नहीं है।यदि मवेशी उस नाले के पानी को क्रास करके निकल जाए तो उनकी त्वचा में घाव हो जाता है। यही पानी ग्राउंड वाटर को दूषित कर रहा है।ये पानी ना तो पीने लायक है और ना ही सिंचाई लायक है। मेरी अध्यक्ष महोदय से मंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि क्या ऐसे उद्योगों के खिलाफ बिना लीपापोती के कार्रवाई होगी।क्या ऐसे उद्योग जो सीधा सल्फ्यूरिक एसिड को सीधा नदी या नाले के पानी में मिला रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा।इसके लिए विधायक जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें जो भ्रमण करके जांच करके कार्रवाई कर सके।

इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं संबंधित विभाग को निर्देशित करता हूं कि ऐसे उद्योग जो सीधा सल्फ्यूरिक एसिड नालों में डाल रहे हैं,उनके जल का परीक्षण करें और सल्फ्यूरिक एसिड रहित जल की प्लांट से निकासी करें ताकि सामान्य जलचर उस पानी में रह सके।

इस जवाब के बाद एक बार फिर विधायक भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने सिर्फ कमेटी बनाकर जांच करने की बात कह रहा है।जिसमें मैं खुद को शामिल नहीं कर रहा।बल्कि विधायक महोदय की अध्यक्षता में दो नगर निगम भिलाई और चरोदा के अधिकारी, राजस्व अधिकारी और एसडीएम मिलकर मौके पर जाकर मुआयना करें और जो भी कार्रवाई हो वो करें।

इसके जवाब में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि ऐसे दो बड़े उद्योग और 28 मंझले उद्योग हैं।जिनमें जांच के बाद अनियमितता पाई गई और कार्रवाई की गई।हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इसके बाद भी यदि ऐसा हो रहा होगा तो कार्रवाई होगी।इसमें सबसे अच्छी कार्रवाई आप कर सकते थे।आपका क्षेत्र है और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं।

समाचार पचीसा
रायपुर, मंगलवार 04 मार्च 2025

जेलेंस्की ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है

शिवकांत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच रूस-यूक्रेन युद्धविराम के मुद्दे पर हुए वाग्युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जेलेंस्की अमेरिका के निमंत्रण पर व्हाइट हाउस गये थे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के बाद यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों के दोहन में अमेरिका की साझेदारी का समझौता होना था। जेलेंस्की खनिजों में साझेदारी देने से पहले अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी लेना चाहते थे। जबकि ट्रंप जेलेंस्की से युद्धविराम की सहमति लेना चाहते थे। बातचीत में गर्मी बढ़ती गयी, जो कहासुनी में तब्दील हो गयी। यह सब मीडिया के सामने हो रहा था। अमेरिकी इतिहास में ऐसी नाटकीय घटना कभी नहीं हुई थी। कहासुनी के बाद खनिज समझौता होने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। इसलिए जेलेंस्की खाली हाथ लौट गये। ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की की मुखरता को अमेरिका का अपमान बताया और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनसे माफी की मांग की। जवाब में जेलेंस्की ने एक अमेरिकी टेलीविजन को दिये इंटरव्यू में कहासुनी पर खेद तो प्रकट किया, पर माफी मांगने से इनकार किया। ट्रंप दो कारणों से जेलेंस्की को पसंद नहीं करते। एक तो 2019 में जेलेंस्की ने ट्रंप का वह अनुरोध ठुकरा दिया था, जो उन्होंने फोन पर किया था। ट्रंप चाहते थे कि जेलेंस्की वह सर्वर अमेरिका के हवाले कर दें, जिसमें उन यूक्रेनियों की गतिविधियां रिकॉर्ड थीं, जिन्होंने कथित रूप से रूसी पहचान बनाकर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप किया था। वे यह भी चाहते थे कि जेलेंस्की बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ जांच बिठायें। फोन पर हुई उसी बातचीत को लेकर ट्रंप पर महाभियोग भी चलाया गया था। इसलिए संभव है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से बदला लेने के लिए बुलाकर खनिज सौदा करने का जाल बिछाया हो। पर इस बात की आशंका तो जेलेंस्की को भी होनी चाहिए थी। वे एक तो शिखर बैठक में जंगी पोशाक पहन कर आये थे, जिस पर ट्रंप ने उनकी अगवानी के समय टिप्पणी भी की थी। दूसरे उन्होंने अपनी आवाज और भाषा पर संयम नहीं रखा। व्हाइट हाउस में उनके न्योते और ट्रंप के साथ बैठक की पृष्ठभूमि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टॉमर ने तैयार की थी। फिर भी यदि वे ट्रंप के साथ खनिज समझौता नहीं करना चाहते थे, तो कोई भी बहाना बनाकर जाना टाल सकते थे। हालांकि ट्रंप ने यह कहते हुए बातचीत का दरवाजा खुला रखा है कि जेलेंस्की जब युद्धविराम के लिए तैयार हों, तब आ सकते हैं। लेकिन इसमें दोराय नहीं कि जेलेंस्की ने अपने ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। फिलहाल फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पोलैंड के नेताओं ने एकता दिखाने के लिए जेलेंस्की का समर्थन किया है, पर जैसे-जैसे हकीकत सामने आयेगी, भावावेश ठंडे पड़ते जायेंगे। नाटो पिछले 75 साल से अमेरिका के दम पर ही सोवियत और रूसी चुनौती का सामना कर पाया है। रूस की परमाणु शक्ति की काट केवल अमेरिका के ही पास है। यूरोप के देश पैसा और हथियार देकर यूक्रेन की आत्मरक्षा की लड़ाई जारी रखने में तो मदद कर सकते हैं, पर रूस को हरा कर यूक्रेन के उस 20 प्रतिशत भाग से वापस नहीं खदेड़ सकते, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यह काम इस धाक के बिना संभव नहीं हो सकता कि अमेरिका अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। पर इसके लिए न अमेरिका की सरकार तैयार है, न जनता। ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराने के लिए इसलिए उतावले हो रहे हैं, ताकि अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों और उनके प्रसंस्करण पर चला आ रहा चीन का वर्चस्व खत्म हो सके। वे यूक्रेन के साथ रूस के दुर्लभ खनिज भंडारों तक भी पहुंचना चाहते हैं, ताकि तकनीक और व्यापार के क्षेत्रों में चीन से आगे रहा जा सके।

बिना अमेरिका रूस का मुकाबला कर पाएगा यूरोप?

अभिनय आकाश

लैटिन भाषा में वर्बा वोलांट, स्क्रिप्टामानेंट नाम की कहावत है। मतलब कहे हुए शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन लिखे हुए शब्द हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये कहावत लगभग 2000 साल पुरानी है। तब आवाज को ऑडियो-वीडियो के माध्यम से कैप्चर करने की तकनीक नहीं थी, लेकिन अब है। दशक गुजर जाते हैं, लेकिन इस दौरान घटित बातें कहे अनकहे रूप में सामने आ ही जाती है। नवंबर 1971 की बात है भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गईं थी। उनका मकसद अमेरिका को ये बताना था कि पूर्वी पाकिस्तान में कितना बड़ा नरसंहार हो रहा है। इसके चलते भारत में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में पूर्वी पाकिस्तान से भागकर लाखों करोड़ों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गाँधी का अपमान किया, 45 मिनट तक उन्हें इंतज़ार करवाया। फिर तीखी बातें भी की। लेकिन उस दौरान इंदिरा ने संयम दिखाते हुए खामोशी बरती। फिर सेना को पाकिस्तान पर हमले का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान और निक्सन दोनों घुटने पर आ गए। राष्ट्र के हित में कई बार निजी अपमान सहने वाला ही असली नेता होता है।

28 फरवरी 2025 को वोलोदिमिर जेलेन्स्की, डोनाल्ड ट्रम्प और जेडी वेंस के बीच जो कुछ भी हुआ उसे देख कर ये बिल्कुल नहीं लगा कि व्हाइट हाउस में डिप्लोमेसी को होते देख रहे हैं। ऐसा लगा मानों समय रैना का इंडिया गॉज लेटेंट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एक्ट के बाद सेल्फ रेटिंग दी भी। उन्होंने कहा भी कि इट इज गोइंग टू बी ग्रेट टेलीविजन। हुआ भी कुछ ऐसा ही, टेलीविजन पर वो छाए हुए हैं और वोलोदिमिर जेलेस्की डैमेज कंट्रोल मोड़ में हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड टूप के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई नोकझोंक पूरी दुनिया में

चर्चा का विषय बना हुआ है। व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब दो राष्ट्राध्यक्षों की इस भिड़त को दुनिया ने देखा। बातचीत का शुरुआती आधा घंटा तो औपचारिकता में बीता, लेकिन आखिर के 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि बातचीत हैसियत दिखाने पर आ पहुंची। सबकुछ विस्तार से बताते हैं। जेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा आपने युद्ध देखा है? वेंस ने कहा कि मैंने न्यूज रिपोर्ट देखी है। जेलेंस्की बोले अमेरिका अभी तो सेफ है, कभी हमला होगा तो पता चलेगा कि युद्ध क्या होता है। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 15 मिनट का पूल स्प्रे (मेहमान नेता के साथ फोटो सेशन) रखा था, लेकिन जेलेंस्की-ट्रम्प में 35 मिनट लंबी बहस छिड़ गई। ट्रम्प का ओवल ऑफिस स्टाफ सन्न रह गया। बहस के बाद ट्रम्प वाइट हाउस के अपने वर्किंग रूम में चले गए।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जेलेस्की से मुलाकात के कुछ घंटों बाद कहा कि वो शख्स शांति नहीं चाहता है। मैं तुरंत संघर्ष विराम चाहता हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शांति समझौते के लिए तैयार प्रतीत होते हैं। व्हाइट हाउस ने पत्रकारों से जेलेस्की के बारे में कहा कि उन्हें पुतिन के बारे में नकारात्मक बाते कहने की जरूरत नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति को यह घोषित करने की जरूरत है कि क्या वह शांति चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी लोग यूक्रेन को पैसे देते हुए थक चुके हैं। वह (जेलेस्की) इस जंग की व्यावहारिक हकीकत को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यह युद्ध कई साल से चल रहा है, उनके देशवासी मर रहे हैं। और जो लोग इस युद्ध के लिए आर्थिक मदद कर रहे है यानी अमेरिकी लोग, वे इस बिल का भुगतान करते-करते थक चुके हैं। परिस्थितियां जेलेस्की के पक्ष में नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में है। ट्रम्प पलटवार करने वाले नेता माने जाते हैं। वो यूक्रेन को अमेरिका की मदद पर रोक का फैसला कर सकते हैं।

स्लोवेनिया, वेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमवर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोलदोवा, स्पेन, पोलैंड, यूके और ईयू ब्लॉक ने समर्थन में पोस्ट किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लिखा कि उन लोगों के प्रति सम्मान, जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी गरिमा, अपनी आजादी, अपने वच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डॉनल्ड टस्क ने कहा कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ट्रंप और जेलेंस्की, दोनों से बतचीत की है। ओवल ऑफिस के इस एपिसोड के बाद से यूरोप में बेचैनी बनी हुई है। यूरोप के देश जेलेंस्की के साथ खड़े हैं और अपनी रणनीति के लिए चर्चा कर रहे हैं। यूरोपीय देश सुरक्षा के ढांचे पर जो चर्चा अमेरिका को भी केंद्र में रखकर करते थे, वह चर्चा अब अमेरिका को अलग करके हो रही है। जानकारों का कहना है कि रूस फायदे में दिख रहा है, लेकिन अमेरिका की इमेज पर इसका असर पड़ेगा। सहयोगी देश विचार करने को मजबूर होंगे कि क्या अमेरिका भरोसेमंद है। ईयू (यूरोपीय यूनियन) के उपाध्यक्ष काजा कलास का कहना है कि %फ्री वर्ल्ड% को अब नए नेता (ट्रम्प नहीं) की जरूरत है। यानी ईयू अब यूक्रेन युद्ध के नाम पर अमेरिका से अपने संबंधों को कम करने की कोशिशों में आगे बढ़ेगा। वैसे भी ट्रम्प ईयू पर 25त्न टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना अमेरिकी सैन्य मदद के यूरोप रूस का सामना कर सकता है? पहली नजर में जवाब सरल लगता है। अमेरिका के बिना भी नाटक के सदस्य देशों की साझा सैन्य शक्ति भी कम नहीं है। 2022 में यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी हमले को रोक दिया था बल्कि उसे पीछे भी ढकेल दिया था। तब के मुकाबले उसकी सैन्य शक्ति अब कहीं ज्यादा है। हालांकि उसने रूसी हमले को रोकने और पीछे ढकेलने में सफलता पाई थी तब यूक्रेन ने रूस का सामना सोवियत काल के पुराने उपकरणों से किया था। इसके मुकाबले रूस जिसके पास करीब 13 हजार टैंकों, 1 हजार लड़ाकू विमानों का जखीरा है वो यूक्रेन के सामने कमजोर नजर आया था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना अमेरिका के भी नाटो रूस का सामना कर सकता है। रूस अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है तो अमेरिका के बिना भी कहीं अधिक विशाल और आधुनिक नाटो बलों के खिलाफ उसकी संभावना बहुत कम दिखती है।

रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रम्प और उपराष्ट्रपति वेंस ने बहुत धीरज दिखाया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, वरना... वे जेलेंस्की पर हाथ भी छोड़ सकते थे। रूस ने जेलेंस्की को बेईमान नेता करार दिया। बहरहाल, इस विवाद के बीच रूस के दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ रूस का यूक्रेन पर अटैक भी जारी है और दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के बाद ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि ट्रंप रूस पर दबाव बना रहे हों। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी बातचीत से यह लगा कि ट्रंप चाहते हैं कि लड़ाई की जो मौजूदा बाउंड्री है, उसमें ही सीजफायर हो जाए, इससे रूस को फायदा होगा। रूस हमेशा से चाहता था कि यूएस से सीधी बातचीत शुरू हो। रूस और अमेरिका साथ बैठकर बात करते हैं तो यह माहौल खत्म होगा कि देखो, रूस को आइसोलेट कर दिया है। इस मुलाकात के दौरान शुरू से ही ट्रंप और जेलेंस्की की पोजिशन में फर्क दिख रहा था। जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिकी रूस के खिलाफ जंग में उन्हें सपोर्ट करें। अगर जेलेंस्की जंग में आगे बढ़ते हैं और यूरोप साथ देता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। न तो ट्रंप और न ही जेलेंस्की इस तकरार को आगे बढ़ाना चाहेंगे और कुछ दिनों में इसका कोई हल जरूर निकल आएगा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

अग्निष्वात्ता, बहिषद, सौम्य और आज्यपा से संयुक्त पितर हैं। इनके साथ दक्ष की पंद्रहवीं कन्या स्वधा का विवाह था, जिस से वयुना और धारिणी नामक दो कन्याएं उत्पन्न हुई। सोलहवीं कन्या का नाम सती था, जो रुद्र से विवाही गई थी, (जिसने तरुण अवस्था में ही दक्ष से रुष्ट होकर उसी के यज्ञ में योगाग्नि से शरीर त्याग दिया का अत:) इससे कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई।

दक्ष प्रजापति नि:सन्देह ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्हीं की असिक्नी नाम वाली दूसरी स्त्री से अन्यान्य कन्याओं के अतिरिक्त अदिति नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो कश्यप के साथ विवाही गई थी।

आगे चलकर इसीसे विवस्वान् पुत्र उत्पन्न हुवा और उसके श्राद्धदेव तथा गनु नाम के पुत्र हुये। यही मनु प्रसिद्ध सूर्यवंश के आदि पुरुष थे। इस प्रकार दक्ष प्रजापति सूर्यवंश के नाना लगते हैं।

इसी तरह दक्ष की दिति नाम कन्या से कश्यप द्वारा दैत्यवंश की उत्पत्ति हुई है जिस वंश में आगे चलकर प्रह्लाद बली आदि अनेक आदर्श-भक्त उत्पन्न हुवे हैं। और भो अनेक कारण दिये जा सकते हैं जिनसे दक्ष का ऐतिहासिक व्यक्ति होना सुनिश्चित है। परन्तु उपर्युक्त उद्धरण में दक्ष की जिन श्रद्धा, मैत्री आदि कन्याओं का उल्लेख मिलता है, उनके पति और पुत्र आदि सब के नामों का समन्वय करने पर कोई भी समझदार अनुष्य इनमें से किसी भी व्यक्ति को ऐतिहासिक शरीरधारी व्यक्ति भानने के लिये तैयार न होगा, कारण कि धर्म के साथ जिन कन्याओं का विवाह होना लिखा है उनके नाग ही यह व्यक्त कर देते ह कि यहां व्यास जी ने धर्म के साथ सम्बद्ध होने वाले श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति आदि 2 गुणों को ही रूपकालङ्कार से पति-पत्नी रूप में वर्णित किया है।

क्रमशः ...

फणीश्वरनाथ रेणु

फणीश्वरनाथ रेणु एक सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। हिंदी कथा साहित्य के महत्त्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु के पिता शिलानाथ मंडल संपन्न व्यक्ति थे। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था। रेणु के पिता कांग्रेसी थे। रेणु का बचपन आजादी की लड़ाई को देखते-समझते बीता। रेणु ने स्वयं लिखा है- पिताजी किसान थे और इलाके के स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता। खादी पहनते थे, घर में चरखा चलता था। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु में उनके पारिवारिक वातावरण से आई थी। रेणु भी बचपन और किशोरावस्था में ही देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। 1930-31 ई. में जब रेणु अररिया हाई स्कूल के चौथे दर्जे में पढ़ते थे तभी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अररिया में हड़ताल हुई। स्कूल के सारे छात्र भी हड़ताल पर रहे। रेणु ने अपने स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर को स्कूल में जाने से रोका। रेणु को इसकी सजा मिली, लेकिन इसके साथ ही वह इलाके के बहादुर सुराजी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। रेणु ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में किया और उसके बाद वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 में रेणु ने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। बाद में रेणु पढने् के लिए बनारस चले गए। बनारस में रेणु ने स्टुडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया। आगे चलकर रेणु समाजवाद से प्रभावित हुए। 1938 ई. में सोनपुर, बिहार में समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रेणु शामिल हुए। इस स्कूल के प्रिंसिपल जयप्रकाश नारायण थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, नरेन्द्र देव, अशोक मेहता जैसे लोगों ने इस स्कूल में शिक्षण कार्य किया था। इसी स्कूल में भाग लेने के बाद रेणु समाजवाद और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए।

समाजवाद के प्रति रुझान पैदा करने वाले लोगों में रेणु रामवृक्ष बेनीपुरी का भी नाम लेते हैं। वह सिर्फ सृजनात्मक व्यक्तित्व के स्वामी ही नहीं बल्कि एक सजग नागरिक व देशभक्त भी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान दिया। इस प्रकार एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इस चेतना का वह जीवनपर्यंत पालन करते रहे और सत्ता के दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। 1950 में बिहार के पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही दमन बढने् पर वह नेपाल की जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ वहां पहुंचे और वहां की जनता द्वारा जो सशस्त्र क्रांति व राजनीति की जा रही थी, उसमें सक्रिय योगदान दिया। दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे रेणु ने सक्रिय राजनीति में भी हिस्सेदारी की। 1952-53 के दौरान वह बहुत लम्बे समय तक बीमार रहे। फलस्वरूप वह सक्रिय राजनीति से हट गए। उनका झुकाव साहित्य सृजन की ओर हुआ। 1954 में उनका पहला उपन्यास 'मैला आंचल' प्रकाशित हुआ। मैला आंचल उपन्यास को इतनी ख्याति मिली कि रातों-रात उन्हें शीर्षस्थ हिंदी लेखकों में गिना जाने लगा। 1975 में लागू आपातकाल का जेपी के साथ उन्होंने भी कड़ा विरोध किया था।

पाकिस्तान की तरह बर्बादी की ओर बढ़ता बांग्लादेश

ललित गर्ग

कहते है कि 'जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ़ भागता है' भले ही यह एक मुहावरा है लेकिन बांग्लादेश पर खरा उतर रहा है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश मुसीबत रूपी पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। 30 लाख बांग्लादेशी लोगों की हत्या करने वाला पाकिस्तान अब दोस्त बन गया है और हर तरह से मदद करने वाला भारत दुश्मन। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढती नजदीकियां, बांग्लादेश का भारत विरोध और पाकिस्तान प्रेम इस मुल्क पर भारी पड़ सकता है और भारी पड़ रहा है। भले ही 54 सालों में पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान सीधा कारोबार शुरू हुआ है। देखने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं और व्यापार ठप्प है। ऐसे में इसका असर भारत पर नहीं पाकिस्तान पर जरूर पड़ा है और वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। बांग्लादेश के लिए भारत जो मायने रखता है, उसकी भरपाई पाकिस्तान तो कतई नहीं कर सकता है। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तानी क्रूरता से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने तमाम कुर्बानियों के बाद जन्म दिया, उसका भारत-विरोधी रवैया दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि विडम्बनापूर्ण कहा जाएगा। भारत से पंगा बांग्लादेश को महंगा पड़ेगा।

अब अगर बांग्लादेश ने तय ही कर लिया है कि भारत से संबंध खराब करने की हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो कुछ भी कहना बेमानी है। जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान की राह पर चलने की ठान ही ली है, तो उनके दुष्परिणाम भी उसे ही भुगतने होंगे। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आम जनता पर दु:खों, परेशानियों एवं समस्याओं के पहाड़ टूटने लगे हैं। वहां जैसी आंतरिक गुटबाजी, प्रशासनिक शिथिलताएं, अराजकताएं और अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमां ने सेना की भूमिका बढ़ाने की बात कही है। उनका संकेत साफ है, यदि अंतरिम सरकार हालात को संभाल पाने में नाकाम रहती है, तो सेना मोर्चा संभालने को तैयार है। दरअसल, शेख हसीना की विदाई के साथ वहां जिस तरह से

राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता बढ़ी है, उसका नुकसान पूरे देश को हो रहा है। न सिर्फ निवेश पर प्रभाव पड़ा है, विदेशी संबंध भी चरमरा रहे हैं, आर्थिक गिरावट तेजी से बढ़ रही है। भारत जैसे देश के साथ सामान्य व्यापार और ढांचागत विकास संबंधी योजनाओं में भी रुकावटें पैदा हुई हैं। बांग्लादेश भारत की सदाशयता एवं उदारता के बावजूद टकराव के मूड में नजर आ रहा है, उसका अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर भी ऐसा ही रवैया है, जिस बारे में वह भले ही अब दलील दे रहा है कि हालिया बांग्लादेश में हिन्दुओं से जुड़ी हिंसक घटनाएं सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से हुई हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों देशों के संबंध बिगाड़ने में पर्दे के पीछे पाकिस्तान की भूमिका साफ है। बांग्लादेश से हाल ही में आई रिपोर्ट चिंताजनक हैं। चल रहे राजनीतिक संकट और राज्य पुलिस की गिरावट ने अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं पर लक्षित हमलों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर दी है। 1947 से, हिंदू आबादी 30 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत से भी कम हो गई है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से स्थिति और खराब हो गई है, जो 2009 से सत्ता में थी। यह संकट पूर्वी पाकिस्तान और आधुनिक बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रत्यक्ष और गुप्त नरसंहार के लंबे इतिहास को दर्शाता है। मंदिरों और पवित्र स्थलों पर 200 से अधिक कथित हमलों सहित वर्तमान हिंसा एक बड़े, निरंतर कट्टरतावादी अभियान का हिस्सा है। हालिया संकट, जो जुलाई 2024 में कथित छात्रों के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ था, उसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और यह दशकों से बढ़ते मुस्लिम कट्टता से जुड़े तनावों को दर्शाता है।

भारत प्रारंभ से बांग्लादेश का सहयोगी एवं हितैषी रहा है, इसी कारण उसने पिछले डेढ़ दशकों में जो आर्थिक तरक्की हासिल की, छह फीसदी से अधिक दर से जीडीपी को बढ़ाया और 2026 तक विकासशील देशों के समूह में शामिल होने का सपना देखा, उन सब पर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार संकीर्णतावादी एवं दुराग्रही सोच के कारण काली छाया मंडराने लगी है। आज कानून-व्यवस्था के सामने समस्या पैदा हो गई है, बांग्ला राष्ट्रवाद की वकालत करने वालों पर खतरा मंडरा रहा है, प्रगतिशील मुस्लिमों एवं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और बंगबंधु व मुक्ति संग्राम के इतिहास को मिटाने का प्रयास हो रहा है। बांग्लादेश की यह गति इसलिए हुई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप चुनौतियों से लड़ पाने में नाकाम हो रही है और भारत से टकराव मोल लेने को तैयार बैठे बांग्लादेश के ऐसे हुक्मरान विवाद के नये-नये मुद्दे तलाश रहे हैं एवं दोनों देशों के आपसी संबंधों को नेस्तनाबूंद कर रहे हैं। आज वहां सांविधानिक, राजनीतिक वैधता का संकट तो गहराया ही है लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य भी धुंधला रहे हैं।

मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग जैसी पार्टियों ने कभी पसंद नहीं किया और अब आमजनता का भी पूरा साथ उनको नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया और शेख हसीना के तख्तापलट की वजह भी बना, तब उनकी मुख्य मांगों में रोजगार प्रमुख रहा, मगर यूनुस सरकार अब इस मोर्चे पर भी फिसड्डी साबित हुई है। उनकी कट्टरपंथी सोच और जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने जैसी पहल को देख उदारवादी छात्र खुद को छला हुआ महसूस करने लगे हैं, इस कारण विश्वविद्यालयों में हिंसा रूकने का नाम नहीं ले रही है। मोहम्मद यूनुस की अपरिपक्व राजनीतिक सोच एवं कट्टरवादी सोच के कारण ही बांग्लादेश ने भारत से दूरियां बढ़ाई है। रस्सी जल गयी पर ऐंठन नहीं गयी की स्थिति में यूनुस भूल गये कि अभी भारत में नरेन्द्र मोदी जैसे कद्दावर एवं सूझबूझ वाले विश्वनेता का शासन है, भारत से दुश्मनी कितनी भारी पड़ सकती है, पाकिस्तान की दुर्दशा से समझा जा सकता है। पाकिस्तान भारत विरोधी अभियान को लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति में अस्थिर बांग्लादेश में चीन एवं पाकिस्तान जैसी तमाम बाहरी ताकतें दखल देने की इच्छुक हैं। इससे दोनों देश बांग्लादेश की जमीन से भारत को घेरना चाहते हैं, बांग्लादेश भी इन षडयंत्रकारी देशों की गिरफ्त में आ गया है और वह भारत विरोध को तीक्ष्ण करने में जुट गया है। भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बना रहा है तो बांग्लादेश समझौते के बावजूद बाधाएं डाल रहा है।

सीमाओं के खुले रहने से बांग्लादेश से लगातार अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, नकली नोटों का कारोबार और आतंकवादी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। विशेषत: पाकिस्तान अब अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये बांग्लादेश का उपयोग कर रहा है। दरअसल, बांग्लादेश की युनूस सरकार पाकिस्तान के इशारों पर पुराने मुद्दे उछाल कर विवाद को हवा दे रही है। निश्चित ही पाक से उसकी बढ़ती नजदीकियां के चलते ही बांग्लादेश में पाक सेना के अधिकारियों की सक्रियता देखी गई है। यूनुस सरकार ने भारत विरोधी तत्वों को न केवल हवा दी है बल्कि उनको उग्र कर दिया है। भारत की उदारता को बांग्लादेश हमारी कमजोरी न मान ले, इसलिए उसे बताना जरूरी है कि भारत से टकराव की कीमत उसे भविष्य में चुकानी पड़ सकती है। यह भी कि संबंधों में यह कसैलापन, दौगलापन एवं टकराव लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसकी यह कटुता उसके लिये ही कालांतर में घातक एवं विनाशकारी साबित हो सकती है। वैसे इसके संकेत मिलने शुरु हो गये हैं। यह विडंबना ही है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से क्षेत्र में शांति व सद्भाव की जो उम्मीदें थी, उसमें उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथ को आगे करके निराश ही किया है। उनकी सरकार लगातार विघटनकारी, अड़ियल व बदमिजाजी का रुख अपनाए हुए है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका भी भारत के साथ बांग्लादेश में सकारात्मक भूमिका निभाने का संकेत दे चुका है। यह दक्षिण एशिया की शांति व समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है।

आज का इतिहास

1905 थियोडोर रूजवेल्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में लिए शपथ लिया।

1908 ट्रांसवाल यूनिवर्सिटी कॉलेज ने प्रिटोरिया विश्वविद्यालय की स्थापना की।

1909 विलियम हॉवर्ड टाफ्ट को संयुक्त राज्य के 27 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

1913 वुडरो विल्सन को संयुक्त राज्य के 28 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

1918 तथाकथित स्पेनिश फ्लू का पहला ज्ञात मामला फोर्ट रिले, कंसास में पहली बार देखा गया था।

1930 फ्रांस में आई भयानक बाढ़ से करीब 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।

1931 ब्रिटिश वायसराय, गवरनोर-जनरल एडवर्ड फ्रेदेरिक्क लिन्द्ले वुड और मोहनदास करमचंद गाँधी जी (महात्मा गाँधी) में भेंट राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के सर्वजन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामे की घोषणा।

1933 फ्रांसिस पर्किन्स को संयुक्त राज्य का श्रम सचिव नियुक्त किया गया था, जिससे उन्हें मंत्रिमंडल की पहली महिला सदस्य बनाया गया था।

1936 जर्मनी में पहली बार हिंडेनबर्ग हवाई जहाज ने आधिकारिक उड़ान भरी।

1941 द्वितीय विश्व युद्ध- ब्रिटिश कमांडोज ने नॉर्वे के लोफोटेन द्वीप पर ऑपरेशन क्लेमोर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

1944 मर्डर, इंक। नेता लुइस बुकाल्टर को हत्या के दोषी पाए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में मौत की सजा पाने वाले एकमात्र राजदूत भीड़ को मार दिया गया।

1972 लीबिया और सोवियत संघ ने एक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये।

1976 द मागिरे को सात विस्फोटकों को रखने के लिए दोषी पाया गया जिससे उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई की।

1977 रोमानिया में भूकंप से 1541 लोगों की मौत हुई।

1980 जिम्बाब्वे अफ्रीकी नेशनल यूनियन के रॉबर्ट मुगाबे को जिम्बाब्वे में पहली सरकार के प्रमुख पद से हटा दिया गया था।

1987 अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविज़न एड्रेस बनाया, जिसमें उन्होंने ईरान-विरोध के चक्कर में अवैध कार्यों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार की।

1989 लंदन के पुर्ले स्टेशन पर रेल दुर्घटना में 5 मृत और 94 घायल हुए।

1991 इराक ने 6 अमेरिकी, 3 ब्रिटिश और 1 इतालवी पीओओ जारी किया।

1997 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मानव क्लोनिंग पर किसी भी शोध के लिए संघीय धन पर रोक लगायी।

तो क्या निशांत की सियासी लॉन्चिंग से वंशवादी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी?

कमलेश पांडे

वंशवादी लोकतंत्र का क्रांतिकारी भूमि बिहार में अपनी गहरी जड़ें जमाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है! यह लोकतंत्र की जननी वैशाली की मूल भावनाओं को मुंह चिढ़ाने जैसा है। ऐसा इसलिए कि सूबाई राजनीति को विगत 4 दशकों तक प्रभावित करते रहने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, जदयू के मुखिया नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार और लोजपा आलाकमान रहे स्व. रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने अपने-अपने लाडले क्रमशः तेजस्वी यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री बिहार, चिराग पासवान, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार और निशांत कुमार, सीएम इन वेटिंग, बिहार को अपनी राजनीतिक विरासत (सियासी जमींदारी) सौंप चुके हैं!

इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही देरी से फैसला किया हो, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद की भांति वो निशांत कुमार के लिए अपने समर्थकों से मजबूत फील्डिंग भी करवा रहे हैं। इससे प्रदेश की राजनीति में कई सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए इन क्षेत्रीय राजनीतिक सूबेदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की राह पर भाजपा का चलना देश की वैचारिक राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जबकि भाजपा को इतनी ऊंचाई देने वाली टीम का मानना है कि चूंकि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत के लिए वो लोग जैसे को तैसा वाली राजनीति देंगे। भाजपा की इसी सोच का फायदा उठाते हुए उसके दो बड़े कद्दावर नेताओं यानी पार्टी में नम्बर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार और नम्बर 3 की हैसियत पर जा चुके राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार भी अपने पुत्रों क्रमशः जय शाह और पंकज सिंह-नीरज सिंह को महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचा चुके हैं। यदि देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा जितने भी यूपीए या एनडीए समर्थक क्षेत्रीय दल हैं, वो भी अपने अपने पुत्रों को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं या ऐसी तैयारी में हैं।

इसलिए कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, सबसे सफल लोकतंत्र को हमारे नेताओं ने वंशानुगत राजतंत्र की तरह ही वंशानुगत लोकतंत्र में तब्दील कर दिया है। यदि कुछ बची-खुची कसर है तो वो गुजश्ते दशक या आने वाले दशक में पूरी हो जाएगी। इसका कारण प्रतिभाशाली डीएनए है या पूंजीवादी षड्यंत्र, यह आपको बाद में पता चलेगा। क्योंकि यूपी के समाजवादी पार्टी प्रमुख रहे स्व. मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश अपनी सत्ता अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्र अखिलेश यादव को सौंप चुके थे। वहीं महाराष्ट्र के शिवसेना प्रमुख रहे स्व. बाला साहेब ठाकरे अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र उद्धव भाऊ ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को सौंप चुके हैं। ये तो महज बानगी भर है, जबकि इसकी फेहरिस्त बड़ी लंबी है।

इसके पीछे अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जब नौकरशाह का बेटा नौकरशाह, न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश, उद्यमी का बेटा उद्यमी बन सकता है तो किसी राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता है! बात में तो दम है, लेकिन भारतीय संविधान भी इस विषय में मौन है! इससे साफ है कि सत्ता की एक अलग सोच होती है जो राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाही में भी लगभग एक समान होती है। यह सोच है वंशवादी सोच, जहां राजा या नेता खुद को महफूज समझता है।

यदि आप आजादी के आंदोलनों, संपूर्ण क्रांति और अन्ना हजारे के आंदोलनों पर गौर करेंगे तो यह साफ पता चलेगा कि इन सबका कुछ अघोषित एजेंडा रहा है, जिसमें व्यक्तिवाद, सम्पर्कवाद और वंशवाद सर्वोपरि है। कहीं यह साफ दिखता है तो कहीं पर यह घुमाफिरा कर, लेकिन मूल मर्म यही कि सत्ता बड़ी बेवफा होती है, इसलिए चाहे जैसे भी हो इसे अपने परिवार के खूंटे से बांधे रहो। नेहरू-गांधी परिवार, संघ परिवार और क्षेत्रीय जातीय राजनीतिक परिवारों की सफलता-विफलता का कारण भी यही है।

हैरत की बात तो यह है कि जो समाजवादी-राष्ट्रवादी 1970-80-90 के दशक तक नेहरू-गांधी परिवार के वंशवाद का विरोध कर रहे थे, और तख्त बदल दो ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो जैसे नारे लगा रहे थे, उन्होंने कैसा क्षेत्रीय वंशवाद चलाया, अब जगजाहिर हो चुका है। हालांकि, इनमें सबसे धैर्यशाली निकले बिहार के कद्दावर मुख्यमंत्री और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने भी जब अपने बेटे निशांत कुमार को सियासत

में उतारने की हरी झंडी दे दी और उनके संग गुलदस्ता वाली फोटो वायरल करवा दिया, तो लोगों के दिलोदिमाग में इस वंशवादी लोकतंत्र को लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं।पहला सवाल यह कि क्या पारिवारिक लोकतंत्र से आम भारतीयों का भला हो पाएगा? दूसरा सवाल यह कि, जो लोग हर बात में ब्राह्मणों या सवर्णों को कोस रहे थे, उन्होंने सत्ताधीश बनने के बाद कैसा आचरण प्रस्तुत किया? तीसरा सवाल यह कि, वंशवादी नेताओं ने अकूत सम्पत्ति जमा करते हुए हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पदाओं को निजी हाथों में सौंपते जा रहे हैं और कोई राजनीतिक चहलकदमी नहीं दिखाई-सुनाई पड़ रही है, क्या इससे आम आदमी का भला होगा? चौथा सवाल यह है कि आरक्षण और सामाजिक न्याय, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रीयता का हश्र आने वाले दिनों में क्या होगा।

यह सवाल इसलिए कि जब तपे-तपाए नेताओं की जगह उनके अनुभवहीन पुत्र ले लेते हैं तो सिस्टम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, जैसा कि उससे उम्मीद किसी भी सभ्य समाज को होती है। इससे पार्टी और नेता, दोनों कमजोर होते हैं। सत्ता से हट जाते हैं। लेकिन जब उनका लक्षित दुरुपयोग एक दूसरे को शह-मात देने के लिए किया जाता है तो स्थिति काफी विकट हो जाती है। भारत और भारतीय जनमानस इसी संक्रमण कालीन स्थिति से गुजर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों, या इन जैसे अन्य नेतागण, जिन्होंने वंशवादी किले को बारीकीपूर्वक जमींदोज किया और खुद मठाधीश बन बैठे।

ऐसे में बिहार में पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुनि चौधरी के पुत्र और मौजूदा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (कुशवाहा जाति) की सियासी धार को कुंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार (कुर्मी जाति) की जो सियासी लॉन्चिंग हो रही है, उससे लवकुश समाज की राजनीति कितनी मजबूत होगी, यह तो वक्त बताएगा।लेकिन जब उम्र गत कारणों से नीतीश कुमार राजनीति से अवकाश लेने के मुहाने पर खड़े हैं, तब उन्होंने अपने पुत्र की सियासी लॉन्चिंग कराकर यह संदेश दिया है कि भाजपा और कांग्रेस चाहे जो मंसूबे पाले, लेकिन बिहार की भावी राजनीति तेजस्वी यादव, निशांत कुमार, चिराग पासवान के ही इर्द-गिर्द घूमेगी।

यही वजह है कि बिहार में निशांत कुमार की शानदार लॉन्चिंग का गुप्त ठेका तेजस्वी यादव ने ले लिया है। उनका यह कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री कहा। हालांकि, एक बार नीतीश पर भोजन की प्लेटें छीन लेने का आरोप भी उन्होंने ही लगाया था। उन्होंने कहा कि बिहार ने अपना मन बना लिया है। इसलिए बीजेपी यहां सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में मौजूद संघी तत्व उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं। दरअसल, विपक्ष के नेता का मानना है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने से जदयू के विलुप्त होने से बच जाने की संभावना है, जो बीजेपी और उसके समर्थकों को पसंद नहीं है। इससे उनकी भावी सियासत का मकसद कोई भी समझ सकता है।

वहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सबसे पहले तो यह साफ होना चाहिए कि चाहे निशांत कुमार हो या कोई और राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय व्यक्ति का अपना होना चाहिए। मेरे माता-पिता (पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी) ने मुझे राजनीति में आने के लिए नहीं कहा था।जबकि मैंने बिहार का दौरा करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता का मूड भांपते हुए खुद यह निर्णय लिया। उन्होंने आगे कहा कि बेशक, अगर निशांत कुमार आगे आते हैं तो जदयू पार्टी को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इसलिए जदयू में मौजूद संघियों की मदद से बीजेपी में कई लोग उनके प्रवेश को रोकने की साजिश में लगे हुए हैं।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री कहा। हालांकि, एक बार नीतीश पर भोजन की प्लेटें छीन लेने का आरोप भी उन्होंने ही लगाया था। मसलन, उन्होंने कई साल पहले नीतीश द्वारा एक रात्रिभोज को रद्द करने की घटना का जिक्र किया। फिर कहा कि पीएम मोदी जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब नीतीश जी ने, जब वो एनडीए में नहीं थे, विधानसभा के भीतर कुछ टिप्पणी की। अब नीतीश जी बीजेपी के सहयोगी हैं और उनके अपमानजनक बयानों से प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा हो गया है। इसलिए बिहार ने अपना मन बना लिया है। बीजेपी यहां सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन वह मोदी और योगी जैसे अपने पोस्टर बॉय भेजकर कोशिश जारी रख सकती है। आखिर में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह उन सभी के लिए आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और बिहार के लोगों ने राजग को वोट नहीं देने का मन बना लिया है, जिसने राज्य पर करीब 20 साल तक शासन किया है। इसलिए उन्होंने हाल ही में भागलपुर दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री पर स्नेह बरसाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मखौल उड़ाया और दोनों नेताओं को पुरानी कटुता की याद दिलाई। दरअसल, बिहार में निशांत कुमार की शानदार लॉन्चिंग का गुप्त ठेका तेजस्वी यादव ने सिर्फ इसलिए ले लिया है कि उन्हें पता है कि जबतक जदयू है, तभी तक राजद की सत्ता में वापसी की संभावना है। और यदि भाजपा, जदयू के गैप को भर देगी तो राजद भी कभी बिहार की सत्ता में नहीं आ पाएगा, पड़ोसी यूपी वाली सपा की तरह।

हालांकि, स्वभाव से सुस्त निशांत कुमार अपने पिताश्री नीतीश कुमार की उम्मीदों पर कितने खरे होंगे, यह तो बिहार विधानसभा चुनाव जनादेश 2025 से ही पता चलेगा। क्योंकि सियासी सफलता के लिए जिस राजनीतिक चतुराई की जरूरत होती है, वह तो उनमें कभी दिखी नहीं। हां, जैसे राजद नेताओं ने राबड़ी देवी को सफल बना दिया, उसी तरह से जदयू नेताओं की फौज निशांत कुमार को भी सफल बना सकती है।

चुनौतियों और सवालों में उलझी ट्रम्प की 'गोल्ड कार्ड' योजना

शोभना जैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से अपने दूसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद एक के बाद कड़े कदम उठा रहे हैं अब उसी कड़ी में ट्रम्प ने अमेरिका की नई वीजा नीति के तहत एक अहम फैसला लेते हुए अमेरिका में बसने और कारोबार करने का सपना देखने वाले विदेशी अमीरों के लिए 'गोल्ड कार्ड' प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में वह अमीर प्रवासियों को आकर्षित करना चाहते हैं, जो अमेरिका में निवेश कर सकें। इस गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के जरिये विदेशियों को लगभग 50 लाख डॉलर देकर अमेरिकी नागरिकता का रास्ता मिलेगा। ये राशि भारतीय रुपए में 43 करोड़ से ज्यादा बैठती है। ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक भारतीयों का बहुत बड़ा वर्ग इस कार्ड के जरिये अमेरिका में बसने की सोच भी नहीं सकता है। ट्रम्प का कहना है कि इस योजना का ब्यौरा अगले दो सप्ताह में तैयार हो जाएगा और मार्च में इसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी संविधान के अनुसार इससे पहले अमेरिका की आव्रजन नीति में किसी अहम बदलाव के लिए कांग्रेस से अनुमति लेनी होगी, तभी इसे ट्रम्प भी मंजूरी दे पाएंगे। वैसे रिपब्लिकन पार्टी का दोनों सदनों में बहुमत है लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह ट्रम्प की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी अनेक सांसद ने इस योजना से असहमति जताई है। वैसे दुनिया भर में लगभग 100 देशों में गोल्ड कार्ड योजना चल रही है लेकिन ब्रिटेन, कनाडा, साइप्रस जैसे अनेक देशों में हुए दुरुपयोग के चलते इसे वापस ले लिया गया। ब्रिटेन ने इसे 2008 में अपने देश में लागू किया था लेकिन यह पाए जाने के बाद कि इस योजना से 'भ्रष्ट अमीरों' को ब्रिटेन में घुसने और वहां इस तरह के अवसर का दुरुपयोग करने का मौका मिल गया, ब्रिटेन ने 2022 में इसे वापस ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईबी-5 प्रोग्राम के तहत पांच से सात साल में नागरिकता मिलती थी जबकि प्रस्तावित 'गोल्ड कार्ड' वीजा योजना में नागरिकता तुरंत मिलेगी। ट्रम्प ने कहा कि 'गोल्ड कार्ड' 35 वर्ष पुराने ईबी-5 वीजा प्रोग्राम की जगह लेगा, जो अमेरिकी व्यवसायों में करीब 1 मिलियन डॉलर का निवेश करने वाले विदेशियों के लिए उपलब्ध है। ट्रम्प के अनुसार इस योजना के तहत यदि दस लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाते हैं, तो यह 5 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर सकता है, जिसे देश के कर्ज को कम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ईबी-5 के तहत आवेदक ऋण ले सकते हैं, जबकि 'गोल्ड कार्ड' वीजा के लिए पहले से ही पूरा नगद भुगतान करना पड़ेगा, जिससे यह भारतीयों के एक बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर हो जाएगा।

ममता ने 'खेला होबे' का आह्वान किया

राहिल नोरा चोपड़ा

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में अपनी पार्टी की संगठनात्मक बैठक में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई और उन्होंने घोषणा की कि राज्य में राजनीतिक लड़ाई और भी तीव्र होगी और एक बार फिर अपने लोकप्रिय नारे 'खेला होबे ' का आह्वान किया। ममता ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखते हुए टी.एम.सी. के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। उन्होंने भाजपा की सीटों की संख्या को कम करने की भी कसम खाई, जिसने 2021 के चुनावों में 77 सीटें हासिल की थीं। जबकि अभिषेक बनर्जी ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ उनके मतभेद हैं और उनके प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि की। हालांकि ममता ने भाजपा पर बाहरी लोगों के नाम जोड़कर पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि डेटा में हेरफेर करने के लिए 'एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स' नामक एक समूह का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गोगोई के राज्य में शीर्ष नेता के रूप में उभरने की अटकलें = कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और ए.आई.सी.सी. के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को नई दिल्ली में असम पी.सी.सी. नेतृत्व के

साथ बातचीत की और असम में पार्टी के आगे के रास्ते पर विस्तृत चर्चा की, जहां पार्टी 2016 से सत्ता से बाहर है। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता (एल.ओ.पी.) राहुल गांधी ने कहा कि असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए राज्य के नेताओं को सामूहिक और एकजुट मोर्चा बनाना चाहिए और आगे कहा कि अगर कोई पार्टी लाइन से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए किसी चेहरे की घोषणा नहीं करेगी लेकिन दिवंगत मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के राज्य में शीर्ष नेता के रूप में उभरने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी ओर, नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य में भाजपा सरकार को उखाड़ फैंकने के लिए उन्हें एकजुट रहने की जरूरत है।

राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के मुद्दे पर, ए.आई.सी.सी. नेतृत्व ने स्थानीय नेतृत्व को आश्वासन दिया कि वे मुख्य रूप से राज्य इकाई की सलाह पर ही चलेंगे। भाजपा के चहेते बने नीतीश = मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को शेष सभी 7 मंत्री पद देकर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और कुल संख्या 36 कर दी, जो 243 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्य में अधिकतम स्वीकार्य है। इनमें से 3 ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग), 2 ई.बी.सी. (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) और 2 सवर्ण (उच्च जाति) हैं। यह विस्तार नीतीश द्वारा मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात के तुरंत बाद हुआ। हालांकि कुछ जद-यू नेताओं ने कहा कि अखिल भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने और अक्तूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करने के सौदे का हिस्सा हो सकता है।

हरियाणा में कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही = कांग्रेस पार्टी ए.आई.सी.सी. में नए सिरे से नियुक्तियों की उम्मीद कर रही है। चर्चा है कि अनुसूचित जाति के एक प्रमुख नेता और सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर को कांग्रेस आलाकमान द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उन्हें राजेश लिलोठिया की जगह ए.आई.सी.सी. एस.सी. विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इस बीच हरियाणा में कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है क्योंकि वह अक्तूबर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के हाथों अपनी चौंकाने वाली हार से उभरने के लिए संघर्ष कर रही है। पार्टी की निरंतर अनिर्णयता, विशेष रूप से हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता (एल.ओ.पी. की नियुक्ति) को लेकर ने इसके विधायकों और कार्यकर्त्ताओं का मनोबल गिरा दिया है। 90 विधायकों वाले सदन में 37 विधायकों के साथ, हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी नेतृत्व शून्यता में है, एक ऐसी स्थिति जिसने नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान सी.एल.पी. को नेता के बिना संघर्ष करना पड़ा और 7 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में भी यही स्थिति रहने की उम्मीद है।

अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया संसद में संजीव अरोड़ा की जगह ले सकते हैं = आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को पार्टी उम्मीदवार बनाया जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया संसद में उनकी जगह ले सकते हैं। जबकि 'आप' ने आधिकारिक तौर पर ऐसी अटकलों का खंडन किया है कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा नामांकन की मांग करेंगे। लुधियाना के उद्योगपति संजीव अरोड़ा 2022 से राज्यसभा के सदस्य हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर अरोड़ा यह उप-चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं तो उन्हें भगवंत मान कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है।

हाशिये पर आ पहुंचा मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व?

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साढ़े ग्यारह प्रतिशत से अधिक माना जाने वाला मुस्लिम संप्रदाय हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक नेतृत्व के गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। कभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा)से कोई मुस्लिम नेता सियासत की कुर्सियों पर आगे बैठा दिखाई देता था, मगर वर्ष 2014 में दोनों दलों के सत्ता से बेदखल होने के बाद से राज्य की एक बड़ी आबादी का कोई अपना नजर नहीं आ रहा है। बीते पांच सालों में महाविकास आघाड़ी और महागठबंधन के सामने आने से चुनावी संघर्ष बहुसंख्यक मतों के बीच जा पहुंचा।

जिससे अल्पसंख्यक समाज के नेता हाशिये पर जा पहुंचे हैं। राज्य में लगभग साठ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मुस्लिम मतदाता अपना प्रभाव रखता है, लेकिन ताजा चुनाव में केवल दस ही विधायक चुनाव जीत पाए। वैसे इतिहास गवाह है कि चुनावी मुकाबलों में मुस्लिमों को अपनी आबादी के हिस्से के बराबर स्थान कभी नहीं मिल पाया।

इसलिए वर्तमान स्थिति को अपवाद नहीं कहा जा सकता है। राज्य विधानसभा के हालिया चुनाव में कुल 420 मुस्लिम प्रत्याशी थे, जो कुल उम्मीदवारों के लगभग 10 प्रतिशत थे। किंतु राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा सीटों के चुनाव में करीब 150 स्थानों पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था, जबकि 50 सीटों पर केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार ने किस्मत आजमाई।

इन सब में से सिर्फ 10 जीतकर विधानसभा पहुंच सके, जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की तुलना में तीन फीसदी से कुछ अधिक थे। चुनाव

में कांग्रेस ने नौ मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें से तीन चुनाव जीते और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने सबसे ज्यादा 14 मुस्लिमों को टिकट दिया, जिनमें से एक ही जीत सका।

इनके अलावा करीब 218 मुस्लिम निर्दलीय भी चुनाव मैदान में थे। इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायकों के जीतने का आंकड़ा 13 है, जो वर्ष 1972, 1980 और 1993 के चुनावों में सामने आया था। वहीं, दूसरी ओर वर्ष 1990 में सिर्फ सात मुस्लिम विधायक बन पाए थे।

विधानसभा के अलावा पिछले 64 वर्षों में प्रदेश से निर्वाचित 614 लोकसभा सांसदों में से केवल 15 या 2.5 प्रतिशत से कम मुस्लिम थे, जो सिलसिला अकोला से वर्ष 1962 में मोहम्मद मोहिबुल हक से आरंभ होकर वर्ष 2019 में इम्तियाज जलील पर आकर समाप्त हो जाता है। इस बीच, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले को रायगढ़ से वर्ष 1989, 1991, 1996, 2004 में लोकसभा में नुमाइंदगी का अवसर मिला। चुनावी राजनीति से अनेक नेताओं के नाम संप्रदाय के नेतृत्व के रूप में सामने आए, लेकिन चुनाव में पराजय मिलने के बाद वे सभी धीरे-धीरे किनारे हो गए हैं।

राज्य में रफीक जकारिया, अंतुले, निहाल अहमद, बाबा सिद्दीकी जैसे नेतृत्व के बाद प्रो। जावेद खान, अमीन खंडवानी, नसीम अहमद, आसिफ जकारिया, हुसैन दलवाई, आरिफ नसीम खान, नवाब मलिक, हसन मुश्रीफ, अबु आजमी, बाबा जानी दुर्रानी, पाशा पटेल, अनीस अहमद, वारिस पठान और इम्तियाज जलील आदि अनेक नाम सामने आते हैं। परंतु कांग्रेस में रहते हुए अनेक नेता अपनी सीमाओं में बंध गए। वही हाल कुछ राकांपा के नेताओं का हुआ। एआईएमआईएम के नेताओं का 'रीचार्ज' पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आवाजाही पर ही निर्भर रहता है। ठीक उसी तरह की स्थिति जो कांग्रेस में पार्टी हाईकमान को लेकर बनी रहती है। लिहाजा जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह विश्वास बनना मुश्किल ही हो चला है।

इसका प्रमाण विधानसभा चुनाव में संप्रदाय के एक वर्ग की नाराजगी के रूप में दिखा था। समाजवादी पार्टी(सपा) के नेता आजमी राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन हर बार गठबंधन के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं, कि खुद का संगठन ही बौना कर देते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम और सपा दोनों ने ही धर्मनिरपेक्ष मतों के लिए गठबंधन के प्रयास किए।

जिसमें ठोस जवाब के अभाव में उन्हें असफलता हाथ लगी। हालांकि आजमी आघाड़ी का हिस्सा बने रहे। कांग्रेस और दोनों राकांपा धर्मनिरपेक्षता का भाव रखते हैं, लेकिन भाजपा-शिवसेना के साथ भगवा मतों के मुकाबले में मुस्लिम नेतृत्व को आगे लाने में संकोच करते हैं। यही वजह है कि दोनों दलों के पुराने मुस्लिम नेता अपनी जगह पर ही सिमट कर रह गए हैं। आगे नए के आने की संभावना ही नहीं दिखती। भाजपा और शिवसेना का शिंदे गुट, दोनों ही राज्य स्तर पर मुस्लिम नेतृत्व को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने पिछली सरकार में मंत्री रहे अब्दुल सत्तार को अपनी नई पारी में मंत्री तक नहीं बनाया। हालांकि राकांपा अजित पवार गुट से हसन मुश्रीफ मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन वह कोल्हापुर तक ही सीमित हैं।

कांग्रेस ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजा, लेकिन उनकी चिंता राष्ट्रीय तथा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अधिक, महाराष्ट्र में कम ही है। उन्हें चुनाव के अवसरों पर ही राज्य में देखा जाता है। राज्य की एक बड़ी आबादी जब भगवाकरण के प्रभाव में कहीं स्वयं को असहज महसूस कर रही है, तो इस स्थिति में मुस्लिम नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह उसे वोट बैंक के बाहर से भी देखे। वह संप्रदाय की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के साथ सेतु बनकर सामने आए। संगठनात्मक रूप से भी कांग्रेस और राकांपा जैसे दल अपने मुस्लिम नेताओं को प्रमुखता तथा नए अवसर देने के लिए आगे आएं। यदि संप्रदाय विशेष का रहनुमा बनकर कोई दल सामने आता है तो धर्मनिरपेक्ष दलों का प्रयास उससे मुकाबला करने का होना चाहिए, न कि हार मान कर किसी कोने में बैठ जाना चाहिए। राज्य के उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में मुस्लिम संप्रदाय की अच्छी आबादी है। यह जानते हुए ध्रुवीकरण और सांप्रदायीकरण से बचाव के लिए एक ईमानदार कोशिश की जानी चाहिए। तभी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ सबका विकास हो पाएगा। वर्ना असंतुलन के परिणाम असंतोष के रूप परिवर्तित होते रहेंगे।

नगा गुटों को छोड़ना होगा अड़ियल रवैया?

शशिधर खान

अलग संविधान, अलग झंडा के साथ 'स्वतंत्र संप्रभु' नगालिम पर अड़े नगा विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (आइसाक-मुइवा) - एनएससीएन (आईएम) ने धमकी दी है कि अगर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से भारत-नगा समझौता जल्द नहीं हुआ तो फिर से भारत के खिलाफ हिंसक लड़ाई छेड़ देंगे। इस गुट के साथ 2015 से केंद्र सरकार का 'फ्रेमवर्क डील' चल रहा है, मगर अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। एनएससीएन (आईएम) से संघर्षविराम सहमति हुए 27 वर्ष गुजर गए। 'फ्रेमवर्क डील' 10वें वर्ष में प्रवेश करने के अब कुछ महीने बचे हैं। 2015 के बाद से यह पहला अवसर है, जब एनएससीएन (आई-एम) ने हिंसा की ओर लौटने की धमकी दी है। लेकिन ये नगा लोग 'अलग झंडा और अलग संविधान' का हठ छोड़ना नहीं चाहते। अभी तक की सारी वार्ताएं बेनतीजा होने का यही असली कारण है। 3 अगस्त 2015 को दिल्ली में एनएससीएन (आई-एम) के साथ हुई 'फ्रेमवर्क डील' में केंद्र के साथ किन बिंदुओं पर सहमति हुई। उसका पूरा खुलासा दोनों पक्षों में से किसी ने नहीं किया है। मगर एनएससीएन (आईएम) एकतरफा प्रचार कर रहा है कि भारत सरकार ने 'संप्रभु नगा राष्ट्रीय झंडा और संविधान' को मान्यता दी है। 'फ्रेमवर्क डील' पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एनएससीएन (आईएम) सुप्रीमो टी। मुइवा ने दस्तखत किए। मुइवा अपने को समानांतर भूमिगत स्वतंत्र संप्रभु नगालिम संघीय सरकार के स्वयंभू 'प्रधानमंत्री' मानते हैं। इस गुट के दूसरे नेता आइसाक चिशी स्वू इस नगालिम सरकार के स्वयंभू 'राष्ट्रपति' थे, जिसका अगस्त, 2015 डील से कुछ दिन पहले दिल्ली में ही निधन हो गया। अब टी. मुइवा को ऐसा 'फाइनल डील' चाहिए, जिसमें भारत के संवैधानिक ढांचे के अंदर समानांतर अलग नगालिम संविधान और झंडा भारत सरकार स्वीकार करे। एनएससीएन (आईएम) ने यह धमकी भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के समय दुहराई है।

कैसे दक्षिणमुखी मकान में नहीं होता दक्षिण दोष

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा के मकान को कुछ परिस्थिति को छोड़कर अशुभ और नकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। दरअसल, हर दिशा में कोई न कोई ग्रह स्थित है जो कि अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। यह निर्भर करता है मकान के वास्तु, मुहल्ले के वास्तु और उसके आसपास स्थित वातावरण और वृक्षों की स्थिति पर।

प्रत्येक ग्रह का अपना एक वृक्ष होता है। जैसे चंद्र की शनि से नहीं बनती और यदि आपने घर के सामने चंद्र एवं शनि से संबंधित वृक्ष या पौधे लगा दिए हैं तो यह कुंडली में चंद्र और शनि की युति के समान होते हैं जो कि विषयोग कहा गया है। आओ जानते हैं कि कैसे दक्षिणमुखी मकान में नहीं होता दक्षिण दोष?

- यदि दक्षिणमुखी मकान के सामने द्वार से दोगुनी दूरी पर स्थित नीम का हराभरा वृक्ष है तो दक्षिण दिशा का असर कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा।
- यदि दक्षिणमुखी मकान के सामने मकान से दोगना बड़ा कोई दूसरा मकान है तो दक्षिण दिशा का असर कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा।
- दक्षिणमुखी मकान का दोष खत्म करने के लिए द्वारा के उपर पंचमुखी हनुमानजी का चित्र भी लगाना चाहिए।
- दक्षिण मुखी प्लाट में मुख्य द्वार आग्नेय कोण में बना है और उत्तर तथा पूर्व की तरफ ज्यादा व पश्चिम व दक्षिण में कम से कम खुला स्थान छोड़ा गया है तो भी दक्षिण का दोष कम हो जाता है।। बगीचे में छोटे पौधे पूर्व-ईशान में लगाने से भी दोष कम होता है।
- आग्नेय कोण का मुख्यद्वार यदि लाल या मरून रंग का हो, तो श्रेष्ठ फल देता है। इसके अलावा हरा या भूरा रंग भी चुना जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मुख्यद्वार को नीला या काला रंग प्रदान न करें।
- दक्षिण मुखी भूखण्ड का द्वार दक्षिण या दक्षिण-पूरब में कतई नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम या अन्य किसी दिशा में मुख्य द्वार लाभकारी होता हैं।
- यदि आपका दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो द्वार के ठीक सामने एक आदमकद दर्पण इस प्रकार लगाएं जिससे घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में बने। इससे घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के साथ घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक उर्जा पलटकर वापस चली जाती है।

क्या कोई युग लाखों वर्ष का होता है

युग क्या होता है इस संबंध में 5 तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। दूसरी बात यह कि भारत के धार्मिक इतिहास को युगों की प्रचलित धारण में लिखना या मानना कितना उचित है? जैसे कि श्रीराम जी त्रैता में और श्रीकृष्ण जी द्वापर में हुए थे। इस तरह तो इतिहास कभी नहीं लिखा जा सकता है। इतिहास को तो तारीखों में ही लिखना होता है और वह भी तथ्य और प्रमाणों के साथ। आओ जानते हैं कि युग की 5 मान्यताएं।

उल्लेखनीय है कि आपने सुना ही होगा मध्ययुग, आधुनिक युग, वर्तमान युग जैसे अन्य शब्दों को। इसका मतलब यह कि युग शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता रहा है। मतलब यह कि युग का मान एक जैसी घटनाओं के काल से भी निर्धारित हो सकता है। तो क्या यह सही है या कि युग की धारणा कुछ और ही है?

पहली मान्यता

युग के बारे में कहा जाता है कि 1 युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17 लाख 28 हजार वर्ष, त्रेतायुग 12 लाख 96 हजार वर्ष, द्वापर युग 8 लाख 64 हजार वर्ष और कलियुग 4 लाख 32 हजार वर्ष का बताया गया है।

दूसरी मान्यता

एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5 हजार वर्षों में पूर्ण हो जाता है।

तीसरी मान्यता

भारतीय ज्योतिषियों ने समय की धारणा को सिद्ध धरती के सूर्य की परिक्रमा के आधार पर नहीं प्रतिपादित किया है। उन्होंने संपूर्ण तारामंडल में धरती के परिभ्रमण के पूर्ण कर लेने तक की गणना करके वर्ष के आगे के समय को भी प्रतिपादित किया है। वर्ष को 'संवत्सर' कहा गया है। 5 वर्ष का 1 युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इद्वत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। 12 युगों के नाम हैं- प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुर्मुख, प्लव, पराभव, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर हैं, उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है। दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवत्सर है।

चौथी मान्यता

ऋग्वेद के अन्य 2 मंत्रों से 'युग' शब्द का अर्थ काल और अहोरात्र भी सिद्ध होता है। 5वें मंडल के 76वें सूक्त के तीसरे मंत्र में 'नहुषा युगा मन्हारजांसि दीयथः' पद में युग शब्द का अर्थ 'युगोपलक्षितान कालान प्रसरादिसवनान अहोरात्रादिकालान वा' किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उदय काल में युग शब्द का अन्य अर्थ अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता था। ऋग्वेद के छठे मंडल के नौवें सूक्त के चौथे मंत्र में 'युगे-युगे विदध्यं' पद में युगे-युगे शब्द का अर्थ 'काले-काले' किया गया है। वाजसनेयी संहिता के 12वें अध्याय की 11वीं कंडिका में 'दैव्यं मानुषा युगा' ऐसा पद आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में देव युग और मनुष्य युग ये 2 युग प्रचलित थे। तैतिरीय संहिता के 'या जाता ओ वधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा' मंत्र से देव युग की सिद्धि होती है।

पांचवीं मान्यता

धरती अपनी धूरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घटी में 1,610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूर्ण करती है। यही धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चन्द्रमास के अनुसार 354 दिनों में सूर्य का 1 चक्कर लगा लेती है। अब सौरमंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल या युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है।

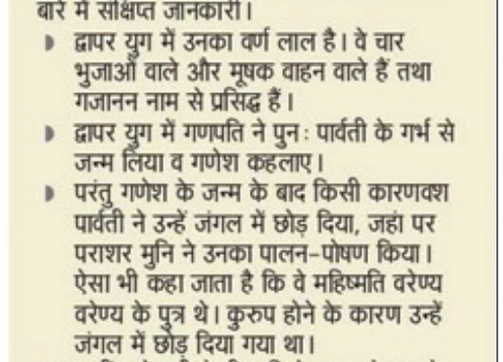

महाभारत काल में हुआ था गणेशजी का गजानन अवतार

मोदक प्रिय श्री गणेशजी विद्या-बुद्धि और समस्त सिद्धियों के दाता हैं तथा थोड़ी उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हिन्दू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उन्हीं का स्मरण और पूजन किया जाता है। गणेशजी ने तीनों युग में जन्म लिया है और वे आगे कलयुग में भी जन्म लेंगे।

धर्मशास्त्रों के अनुसार गणपति ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। अष्ट विनायक की भी प्रसिद्धि है। आओ जानते हैं उनके द्वापर के अवतार गजानन के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

- द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है। वे चार भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं।
- द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती के गर्भ से जन्म लिया व गणेश कहलाए।
- परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन-पोषण किया। ऐसा भी कहा जाता है कि वे महिष्मति वरेण्य वरेण्य के पुत्र थे। कुरुप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था।
- इन्हीं गणेशजी ने ही ऋषि वेदव्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी।
- इस अवतार में गणेश ने सिंदुरासुर का वध कर उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त कराया था।
- इसी अवतार में गणेश ने वरेण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया।

सुनसान जगह पर नहीं रहना चाहिए घर

हिन्दू पुराणों और वास्तु शास्त्र में कुछ जगहों पर एक सभ्य व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि वह वहां रहता है तो निश्चित ही उसके जीवन और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। घर यह सुकून का नहीं है तो कैसे जीवन में सुकून आएगा। जैसे चौराहे, तिराहे, अवैध गतिविधियों वाली जगह, शोर मचाने वाली दुकान या फैक्ट्री आदि। इन्हीं में से एक है सुनसान इलाका। दरअसल, आप जहां रहते हैं उस स्थान से ही आपका भविष्य तय होता है। यदि आप गलत जगह रह रहे हैं तो अच्छे भविष्य की आशा मत कीजिये। आओ जानते हैं कि क्यों नहीं रहना चाहिए सुनसान जगह पर।

- दो तरह के सुनसान होते हैं एक मरघट की शांति वाले और दूसरे एकांत की शांति वाले। कई लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसके चलते वे सुनसान में रहने चले जाते हैं। सुनसान जगह पर रहने के कई खतरें हैं और साथ ही शास्त्रों में ऐसी जगहों पर रहने की मनाही है।
- भविष्य पुराण अनुसार आपका घर नगर या शहर के बाहर नहीं होना चाहिए। गांव या शहर में रहना ही तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित होता है।
- यदि घर बहुत सुनसान स्थान पर या शरह-गांव के बाहर होगा तो जब भी आप घर से बाहर कहीं जाएंगे उस दौरान आपके मन और मस्तिष्क में घर-परिवार की चिंता बनी रहेगी।
- यह तो आप भी जाते होंगे कि सभी सुनसान स्थान पर अपराधी आसानी से अनिष्ट संबंधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।
- दूसरी बात यदि शहर से दूर घर है तो रात-बिरात आने जाने में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भले ही आपके पास कार या बाइक हो।
- सुनसान जगहों को राहु और केतु की बुराई का स्थान माना जाता है। यहां पर घटना और दुर्घटना के योग बने रहते हैं।
- सुनसान जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार बहुत तेजी से पनपते हैं।
- जहां अस्पताल, विद्यालय, नदी, तालाब, स्वजन या मनुष्य की आबादी नहीं है वहां पर नही रहना चाहिए।

कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार

घर के दरवाजे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार हम मकान खरीदते वक्त या बनवाते वक्त यह ध्यान नहीं देते हैं कि किस प्रकार के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। घर का मुख्य द्वार वास्तु अनुसार होता है तो कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बेहतर होगा कि दरवाजा शीशम या सागौन की लकड़ी और धातु का बना हो। दरजावा किसी भी प्रकार सा टूटा फूटा या तिरछा नहीं होना चाहिए। द्वार के खुलने बंद होने में आने वाली चरमराती ध्वनि स्वरवेध कहलाती हैं जिसके कारण आकस्मिक अप्रिय घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। आओ जानते हैं कि घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए।

- एक सीध में तीन दरवाजे नहीं होना चाहिए।
- दरवाजे के भीतर दरवाजा नहीं बनाना चाहिए।
- एक पल्ले वाला दरवाजा नहीं होना चाहिए। दो पल्ले वाला हो।
- ऐसा दरवाजा नहीं होना चाहिए जो अपने आप खुलता या बंद हो जाता हो।
- घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलने वाला नहीं होना चाहिए।
- कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें खिड़कियां होती हैं ऐसे दरवाजों में वास्तुदोष हो सकता है।
- मुख्य द्वार त्रिकोणाकार, गोलाकार, वर्गाकार या बहुभुज की आकृति वाला नहीं होना चाहिए।
- मुख्य दरवाजा छोटा और उसके पीछे का दरवाजा बड़ा नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजा बड़ा होना चाहिए।
- घर के ऊपरी माले के दरवाजे निचले माले के दरवाजों से कुछ छोटे होने चाहिए।
- घर में दो मुख्य द्वार हैं तो वास्तुदोष हो सकता है। विपरीत दिशा में दो मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए।

सूर्योपासना के समय जपें ये खास मंत्र

महिलाओं को रविवार और सोमवार को सूर्योपासना से घर में समृद्धि व गर्भवती महिलाओं को गुणी पुत्र की प्राप्ति होती है। बह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इन दिनों में खेजड़ी के पेड़ के नीचे प्रातः काल सूर्योपासना करते हुए इस मंत्र का 51 बार जाप करने से लाभ मिलता है-

नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः।
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तु ते।।
ओम आदित्याय नमः।

आत्मबल, बुद्धि, इन्द्रियों में सौम्यता, शिष्टता, काम, क्रोधादि शमन व मानसिक पीड़ा से मुक्ति के लिए इन महीनों में आने वाले हर रविवार को खेजड़ी के नीचे सूर्य के सामने बैठ इस मंत्र का 51 बार वाचन करें। पेड़ के नीचे की मिट्टी को लाकर घर में फेंकना शुभ होता है।

ओम नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः।।
ओम सूर्याय नमः।

जिन महिलाओं को संतान सुख न हो, ऐसी महिलाओं को आंवले के पेड़ के नीचे अथर्ववेद के इस मंत्र का 101 बार जाप व सूर्य देव को जल सिंचन करने से संतान प्राप्ति सुख संभव है-

परिहस्त विधारय योनिं गर्भाय धातवे।
ओम भास्कराय नमः।

नीलें रंग के अपराजिता (विष्णुकान्ता) नामक पौधे के नीचे इस मंत्र का जाप करने से घर के मुकदमेबाजी व न्यायालय में विजय, घर में समृद्धि व स्नायु तंत्र (नर्वस सिस्टम), चर्म रोग व श्वसन संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। इस पौधे के न होने की दशा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य को जल सिंचन कर इस मंत्र का 101 बार जाप करें -

ओम विश्वानिदेव सवितुः दुरितानि परासुवः
यद् भद्रं तन्नासुवः। सूर्य कृणोतु भेशजं
चन्द्रमा वोपोच्छतु।।
ओम सूर्याय नमः।

दीर्घायु व हृदय संबंधी बीमारियों के लिए आश्विन व कार्तिक मास के प्रति रविवार बड़, ढाक, अशोक या सूर्यमुखी पौधे के नीचे आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें या अथर्ववेद के इस मंत्र का 51 बार जाप करें -

उत सूर्योदिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन।
ओम भानवे नमः।

कुशाग्र बुद्धि, इंटरव्यू में सफलता व शिक्षा से जुड़े पक्षों तथा वायु संबंधी रोगों के निवारण के लिए अथर्ववेद के इस मंत्र का पीपल के पेड़ के नीचे प्रातः काल हर रविवार इस मंत्र के जाप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पुरुषः।
त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नोअसियज्ञिया।।
ओम सूर्याय नमः।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विश्व वन्यजीव दिवस पर मोदी ने लायन सफारी का आनंद उठाया

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात की तीन दिन की यात्रा पर है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर पहुंचे है। विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने सोमवार की सुबह जूनागढ़ जिले में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेर सफारी की है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। यहां से आने के बाद नरेंद्र मोदी रात भर सासन में राज्य वन विभाग के गेस्ट हाउस में रुके है। यहीं से पीएम मोदी शेर सफारी करने गए है। इस शेर सफारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, आज, विश्व वन्य जीवदिवस पर, आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने रोहित शर्मा पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

नईदिल्ली। कांग्रेस ने अपनी प्रवक्ता शमा मोहम्मद को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सोमवार को फटकार लगाई और उन्हें अपना संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने तथा भविष्य में सावधानी बरतने का निर्देश दिया। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि शमा की टिप्पणी कांग्रेस का मत नहीं है। शमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रविवार देर रात पोस्ट किया था जिसे उन्होंने अब हटा दिया है। उनके इस पोस्ट पर भाजपा नेताओं सहित कई लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार विजय हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी के बारे में शमा मोहम्मद की टिप्पणी पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाती है।

रोहित शर्मा पर कांग्रेस की टिप्पणी पर भाजपा ने की निंदा

नईदिल्ली। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जो लोग राहुल गांधी की कप्तानी में 90 चुनाव हार चुके हैं, वे रोहित शर्मा की कप्तानी को अप्रभावी कह रहे हैं! उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली में 6 बार शून्य पर आउट होना और 90 बार चुनाव हारना प्रभावशाली है, लेकिन टी20 विश्व कप जीतना उतना प्रभावशाली नहीं है! वैसे रोहित का कप्तान के तौर पर शानदार रिकॉर्ड है! पूनावाला ने कांग्रेस नेता की इस तरह की टिप्पणी की भी आलोचना की, जबकि पार्टी ने खुद को मोहब्बत की दुकान- प्यार की दुकान के रूप में ब्रांड किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी वास्तव में - नफ़रत के भाईजान- नफरत के दूत हैं। पूनावाला ने कहा, भारत, इसकी संस्थाओं और इसकी सशस्त्र सेनाओं का विरोध करते हुए - बार-बार यह कहते हुए कि वे भारतीय राज्य के खिलाफ हैं- कांग्रेस अब भारतीय टीम के भी खिलाफ हो गई है।

मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया

लखनऊ। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भतीजों के साथ नहीं बनती। आकाश आनंद को बसपा में सभी पदों से मुक्त करने से पहले मायावती अखिलेश यादव को भी झटका दे चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें आगे बढ़ाया लेकिन ऐन चुनावों के बीच ही उन्होंने आकाश आनंद के पर कतर दिये थे। हम आपको याद दिला दें कि मायावती के उत्तराधिकारी के नाते आकाश आनंद ने जब लोकसभा चुनाव प्रचार में धुआंधार रैलिया करनी शुरू की थीं तो उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ रही थी और मीडिया भी उन्हें खास तवज्जो देने लगा था। उस समय आकाश आनंद ने एक रैली के दौरान हिंसा भड़काने जैसा बयान दिया तो मायावती ने उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें परिपक्व होने तक घर बिठाने का निर्णय कर लिया। देखा जाये तो आकाश आनंद ने जो कहा था वह गलत था।

मोदी सरकार ने स्टालिन के आरोपों का दिया जवाब

नईदिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 किसी भी राज्य पर हिंदी को लागू नहीं करती है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि इस नीति का तमिलनाडु सरकार का विरोध राजनीति से प्रेरित था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधान ने स्पष्ट किया कि एनईपी मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने बताया, हमने एनईपी 2020 में कभी नहीं कहा कि केवल हिंदी होगी। शिक्षा मूल भाषा में होगी। तमिलनाडु में, यह तमिल होगी। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु सरकार एनईपी 2020 की तीन-भाषा नीति का विरोध कर रही है। राज्य ने क्षेत्रीय भाषाओं पर नीति के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। प्रधान ने ऐसी चिंताओं को राजनीतिक कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, एनईपी 2020 हिंदी, तमिल, उड़िया और पंजाबी सहित सभी भाषाओं पर प्रकाश डालता है। सभी भाषाओं का समान महत्व है।

सामने आया उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी के साथ इस तरह के गठबंधन की न तो कोई गुंजाइश है और न ही इसकी कोई जरूरत है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके विचार काफी अलग हैं। जम्मू-कश्मीर बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम (भाजपा के साथ) किसी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, न तो इसकी कोई गुंजाइश है और न ही इसकी जरूरत है। हमारे विचार भी मेल नहीं खाते।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो हमारे विचार बहुत अलग हैं। हम (सत्र के दौरान) हर चीज पर चर्चा करेंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार लोगों से किये गये सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कथित तौर पर छाया मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) गठित करने की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा, ''हमारे देश में सिर्फ एक ही मंत्रिमंडल है। कोई 'छाया मंत्रिमंडल' नहीं है। अब तक यहां भाजपा ने राज किया है। अब जनता की सरकार अपना काम करेगी।''

अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''छाया (मंत्रिमंडल) की कोई जरूरत नहीं है। हमने लोगों से उनकी उम्मीदों को पूरा करने का वादा किया है और हम अपने वादों पर कायम हैं।'' मुख्यमंत्री ने गुलाम सिब्तैन मसूदी के निवास पर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की, जिनका इस सप्ताह की शुरुआत में निधन हो गया था। मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी के भाई और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक के ससुर थे।

बिहार बजट : आधी आबादी पर जोर महिलाओं के लिए बड़े ऐलान

पटना। बिहार सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिनके पास वित्त विभाग भी है। यह पिछले बजट 2,79 लाख करोड़ रुपये से 38,169 करोड़ अधिक है। बजट पेश करते हुए चौधरी ने कहा कि कैंसर केयर सोसायटी बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बेगुसराय में एक कैंसर अस्पताल खोलेगी क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसर मरीज इसी जिले से हैं।

चुनावी साल में बजट का फोकस महिलाओं पर रहा है। इसमें वीमेन हाट, महिलाओं के लिए जिम और गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के %सबका साथ सबका विकास% के सिद्धांत और सीएम के %न्याय के साथ विकास% के सिद्धांत पर आधारित है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में शिक्षा पर 60,954 करोड़, स्वास्थ्य पर 20,335, ग्रामीण विकास पर 16,193 और ऊर्जा पर 13,483 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकार पटना में %महिला हाट% भी स्थापित करेगी और राज्य की सभी पंचायतों में %कन्या विवाह मंडप% बनाये जायेंगे। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी है। चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा, इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। राज्य के प्रमुख शहरों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। इन केंद्रों में प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। सरकार धार्मिक पर्यटन पर फोकस करेगी और महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा होने वाला है. अगले तीन महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ान भरने लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी घोर विरोधी रहे सम्राट चौधरी के राज्य के वित्त मंत्री के तौर बजट पेश किये जाने के बाद उनके बगल में बैठे जदयू के प्रमुख ने अपनी सीट से खडे होकर चौधरी को शाबाशी दी। बजट में कहा गया है कि किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सतत् औद्योगिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्य में रोजगार के नये अवसर विकसित करने के उद्देश्य से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025 लाई जाएगी।

चौधरी ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों के लिए वृहत संभावना है. जिसको बढ़ावा देने में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। इससे राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाददर्दा आधारित इनपुट के लिए किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, इन उत्पादों के आधार पर होने वाले मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया में रोजगार के कई अवसर भी सृजित होंगे। इसमें कहा गया है कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। सम्पूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में बिहार राज्य के सभी 9 प्रमण्डलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केन्द्रों को स्थपित किया जाएगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैसर केयर सोसाईटी की स्थापना की जायेगी। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा 1 से ङ्ग तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जायेगा, जिसपर प्रतिवर्ष अतिरिक्त 875.77 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज!

- वीरप्पा मोइली का बयान, शिवकुमार को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता

बेंगलुरु। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. एम वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस के कुटुम्बोत्सव कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में सीएम की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गुट आमने-सामने है। डी के शिवकुमार की उपस्थिति में बोलते हुए, मोइली ने शिवकुमार को पहला विधायक टिकट दिलाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि वह एक सफल नेता के रूप में उभरे हैं।

मोइली ने करकला और गोम्मटेश्वर की पवित्र भूमि के बीच तुलना करते हुए घोषणा की, उन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिवकुमार का नेतृत्व श्रद्धेय जैन देवता की तरह फलेगा-फूलेगा। उन्होंने कहा कि आपने (डीके शिवकुमार) अच्छा नेतृत्व दिया है। आपने पार्टी बनाई है। लोग बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन आपको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसे लेकर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आपको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री बनना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे उपहार के रूप में दिया जाना चाहिए, यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने कड़ी मेहनत से अर्जित किया है।

मोइली ने विशेषकर चुनौतीपूर्ण समय में शिवकुमार के नेतृत्व की सराहना की। मोइली ने पार्टी के पुनर्निर्माण में शिवकुमार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने संकट के दौरान पार्टी को पुनर्जीवित किया और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस को फिर से सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवकुमार के खिलाफ की गई आलोचनाओं के जवाब में मोइली ने विपक्ष की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी टिप्पणियां अक्सर व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए की जाती हैं। मोइली ने आगे इस बात पर जोर दिया कि उन्हें रोकने के किसी भी प्रयास के बावजूद, यह अपरिहार्य था कि शिवकुमार यह भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस नेता डॉ एम वीरप्पा मोइली के बयान के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कार्यकर्ताओं की बैठक में था।

खेल
प्रमुख समाचार

ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदली टीम बढ़ सकती है भारत की मुश्किलें!

दुबई। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अपनी टीम में आखिरी समय में बदलाव करते हुए चोटिल मैथ्यू शॉर्ट की जगह युवा ऑलराउंडर कूपर कोनोली को शामिल किया है। दुबई की पिच पर सेमीफाइन में कूपर कोनोली ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। अगर कूपर कोनोली को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो इससे भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

कूपर कोनोली एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं, जिनका जन्म 22 अगस्त, 2003 को पर्थ में हुआ था। वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। उन्होंने 2022 के अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने बल्लेबाजी में 74.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 6 पारियों में कुल 74 रन बनाने में कामयाबी हासिल की थी।

मैथ्यू शॉर्ट को अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप-स्टेज मैच के दौरान चोट लग गई थी। जिससे मैदान पर फील्डिंग करते समय वह परेशानी में नजर आये। हालांकि बाद में लाहौर में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 21 वर्षीय ऑलराउंडर कूपर कोनोली को टीम में शामिल किया है। कोनोली बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर हैं, जिन्होंने तीन वनडे सहित छह अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

सेमीफाइनल के लिए बदली हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, आरोन हार्डी, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर संघा, एडम जाम्पा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 112 अंक गिरा; निफ्टी 22,120 पर लगभग फ्लैट बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में करेक्शन का दौर सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार (3 मार्च) को भी जारी रहा और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए। पॉजिटिव शुरुआत के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवीवेट शेयरों के साथ विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार लाल निशान में बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 200 से ज्यादा अंक चढ़कर 73,427 अंक पर ओपन हुआ। यह 73,649 अंक तक चढ़ गया था। हालांकि, आधे घंटे के बाद यह लाल निशान में फिसल गया। अंत में सेंसेक्स 112.16 अंक या 0.15% गिरकर 73,085.94 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी मजबूती के साथ 22,194 अंक पर खुला। हालांकि, कुछ ही देर में यह भी लाल निशान में चला गया। अंत में निफ्टी 5.40 अंक या 0.02% की मामूली गिरावट लेकर 22,119.30 पर क्लोज हुआ।

क्या टैक्स कम करने से FIIs भारतीय शेयर बाजार में लौटेंगे?

नईदिल्ली। सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स में कटौती करने या इसे खत्म कर देने, चाहे वह लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, से विदेशी निवेशकों (FIIs) को भारतीय शेयर बाजार में वापस लाने के लिए काफी नहीं होगा। एनॉलिस्ट्स का मानना है कि यह सही दिशा में एक कदम जरूर है, लेकिन विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपायों की जरूरत होगी। कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा, कैपिटल गेन टैक्स में कटौती से निवेशकों का टैक्स के बाद रिटर्न बढ़ेगा,लेकिन सिर्फ टैक्स कम करने से विदेशी निवेशकों की वापसी सुनिश्चित नहीं होती। हमें अन्य उपायों पर भी ध्यान देना होगा। शाह का कहना है, सरकार कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपाय लागू कर विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।

मुश्किल में फंसी रिलायंस की ये कंपनी, लग सकता है जुर्माना

नईदिल्ली। अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक कंपनी पर बैटरी सेल प्लांट स्थापित करने में विफल रहने के बाद जुर्माने लगने का खतरा मंडरा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की पीएलआई योजना के तहत रिलायंस की न्यू एनर्जी लिमिटेड ने एक बोली जीती थी। यह बोली बैटरी सेल निर्माण के लिए थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी प्लांट स्थापित करने की समय सीमा से चूक सकती है। इस स्थिति में कंपनी को 125 करोड़ रुपये या 1.43 करोड़ डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और अन्य कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड पर भी इतना ही जुर्माना लग सकता है। कंपनी ने बैटरी सेल बनाने के लिए पीएलआई योजना तहत आवेदन किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि रिलायंस ग्रुप के लिए यह मौद्रिक जुर्माना भरना कोई बड़ी बात नहीं है।

शाओमी 15 और शाओमी 15 अल्ट्रा की धमाकेदार लॉन्चिंग

नईदिल्ली। चीनी स्मार्टफोन मेकर शाओमी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन शाओमी 15 सीरीज को ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है। कंपनी ने इस सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन शाओमी 15 और शाओमी 15 अल्ट्रा लॉन्च किए हैं। यह नई सीरीज पिछले साल की शाओमी 14 सीरीज का सक्सेसर है। दोनों स्मार्टफोन्स का डिजाइन काफी आकर्षक है। खासतौर पर, शाओमी 15 अल्ट्रा अपने टू-टोन फिनिश के कारण अलग ही नजर आता है। दोनों स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है और इनका कैमरा सिस्टम Leica के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। बता दें कि शाओमी 15 अल्ट्रा को चीन में 27 फरवरी को लॉन्च किया गया था, जबकि शाओमी 15 पिछले साल अक्टूबर में चीन में डेब्यू कर चुका है।

बढ़ती खपत करेगी टैरिफ का मुकाबला

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 'भारतीय अर्थव्यवस्था की नई स्थिति' पर प्रकाशित दो रिपोर्टों को गंभीरतापूर्वक पढ़ा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की फरवरी 2025 की बुलेटिन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की रिसर्च रिपोर्ट में एकमत से कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी के जोरदार संकेत विकास दर को बढ़ाने वाले सकारात्मक संदेश हैं। इन रिपोर्टों के अलावा, इन दिनों भारतीय बाजारों में मांग और खरीदारी तथा महंगाई विषय पर प्रकाशित हो रही रिपोर्टों में भी कहा जा रहा है कि सरकार के पूंजीगत खर्च बढ़ने, ग्रामीण मांग के साथ-साथ शहरी मांग में सुधार और महंगाई में कमी से अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है।

आरबीआई के बुलेटिन में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के उच्च आवृत्ति संकेतक मसलन, वाहन की बिक्री, हवाई यातायात, इस्पात खपत आदि देश की गतिविधियों में छमाही आधार पर वृद्धि का संकेत दे रहे हैं और इन गतिविधियों में आगे भी तेजी की संभावना है। कहा गया है कि विकास के चार इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर आगामी वर्ष 2025-26 बजट में किए उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह भी कहा गया है कि यद्यपि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती और व्यापार नीति से डॉलर मजबूत हो रहा है। इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी की निकासी बढ़ सकती है, लेकिन इन सबके बीच आर्थिक गतिविधियों की गति बरकरार रहने की

उम्मीद है। कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन से ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित आयकर राहत के बीच मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ खर्च योग्य आय में वृद्धि को देखते हुए शहरी मांग में भी बड़े सुधार की उम्मीद है।

इसी तरह एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ लगाने से निर्मित विपरीत वैश्विक आर्थिक हालात के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नई मजबूत आर्थिक संभावनाएं हैं। ग्रामीण इलाकों में कृषि मजदूरी लगातार बढ़ रही है। ट्रैक्टरों की बिक्री और रबी फसलों की बुआई में तेजी आई है। देश भर में अक्तूबर से दिसंबर 2024 के बीच पूंजीगत खर्च तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में जुलाई से सितंबर 2024 की तिमाही में जो विकास दर महज 5.4 फीसदी ही थी, वह अक्तूबर से दिसंबर 2024 के बीच बढ़कर 6.3 फीसदी अनुमानित है।

एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जबकि एलएंडटी के अनुसार, यह वृद्धि दर 6.7 फीसदी रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.2 फीसदी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। निस्संदेह देश में महंगाई दर घटने से भी विकास दर को गति मिल रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जब इस समय दुनिया के कई देशों में महंगाई बेकाबू बनी हुई है, तब भारत में महंगाई घट रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने स्वीकार किया है कि हम दुनिया में वर्ष 2024 तक महंगाई पर काबू पाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए अब हम दुनिया में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए हरसंभव नए प्रयास करेंगे। ज्ञातव्य है कि भारत में जनवरी 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) घटकर 4.3 फीसदी के स्तर पर आ गई है, जो पिछले पांच महीनों में सबसे निचला स्तर है। इसी तरह जनवरी 2025 में थोक मुद्रास्फीति 2.31 फीसदी रही है। इस तरह महंगाई घटना विकास के लिए लाभप्रद और सुकूनदेह परिदृश्य है।

इसके अलावा, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती और केंद्रीय बजट में करदाताओं को टैक्स में मिली राहत से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ वाला बजट हुआ पेश : डिप्टी सीएम अरुण साव

- बजट 2025 से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी गति, गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन 2047 के लक्ष्य को करेंगे प्राप्त : उप मुख्यमंत्री अरुण साव
- सांय-सांय विकास, अंतिम व्यक्ति की चिंता का प्रयास वाला बजट - डिप्टी सीएम अरुण साव
- छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विकसित छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ। बजट में रजत जयंती की झलक साफ तौर पर दिखी। यह बात उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कही। उन्होंने कहा कि,वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने विधानसभा में गति (ब्रज्ञद्ध) बजट पेश किया है। गति के ब्र गुड गवर्नेंस, ख एक्सलरेटिंग, ज्ञ टेक्नोलॉजी और द्ध इंडस्ट्रियल ग्रोथ से मुख्यमंत्री विष्णु देव जी के विकसित प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने कुल 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया गया।

छत्तीसगढ़ इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष मना रहा है। और छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है।

श्री साव ने कहा कि, बजट 2025 में हमारी सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए पीएम आवास 8500 करोड़ रुपए बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दी है। जबकि मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए, न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया है।मुख्यमंत्री नगरों उठान योजना शुरू की गई है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज, 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल मुक्त करने 3200 बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू किया है, जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था। इस बजट में यात्रा के लिए 15 करोड़ रखा गया है। वहीं हक त्याग, बंटवारा में किसानों का लाखों रूपये खर्च होते हैं। इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती थी, इसे रोकने के लिए इसका शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है।

छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है: किरण सिंह देव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश सरकार के बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का अभिनंदन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री श्री चौधरी द्वारा बहुस्पर्शी, बहुआयामी और सर्वव्यापी बजट पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। श्री देव ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया है। श्री देव ने कहा इस बजट में विशेषकर बस्तर, सरगुजा ,वनवासी क्षेत्र , आदिवासी अंचल , जहां पर विकास की अनेक संभावनाएँ हैं, उसे उचित स्थान दिया गया है।

श्री देव ने कहा इस बजट में विकास के कई कार्यक्रम व योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, युवाओं की दृष्टि से हो, मातृ शक्तियों का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से हो चाहे किसान भाइयों के लिए हो और उद्योग की दृष्टि से चाहे वह बड़े उद्योग हो लघु उद्योग हो मध्यम उद्योग हो ,इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ के पाँचों संभाग में समुचित रूप से विकास के अनेक प्रावधान किए गए है , जो बजट में घोषित योजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुई हैं। श्री देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप 2047 तक विकासशील भारत को विकसित देश में परिवर्तन करने की दृष्टि से जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं बनाई है, मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में और पूरे छत्तीसगढ़ में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने की दृष्टि से यह उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पिछला बजट ज्ञान पर समर्पित था और इस बजट में ज्ञान को गति प्रदान करने की दृष्टि से अनेक प्रावधान किए गए हैं।

साय सरकार के बजट ने राज्य की जनता को निराश किया :बैज

- बजट से साफ साय सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा, रोजगार और कृषि नहीं

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिना किसी ठोस योजना के सतही कल्पनाओं पर आधारित नीरस बजट है। ऐसा लग रहा था वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट नहीं मोदी की चरण वंदना कर रहे थे। साय सरकार का बजट आम जनता के अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक रहा है, ना इसमें युवाओं के रोजगार के संदर्भ में कोई रोड मैप दिख रहा है, ना ही महंगाई से निपटने कोई ठोस रणनीति है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कुछ नहीं है। मोदी की गारंटी में किये गये वादे 1 लाख नौकरियों के सृजन के बारे में इस वर्ष के बजट में भी कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए 500 रू. में सिलेंडर देने के बारे में बजट में कुछ नहीं है। पिछले बजट में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किये थे एक भी भर्ती नहीं कर पाये। इस वर्ष फिर से 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समाज के लिए बजट में कुछ नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए, बजट में कुछ भी नया नहीं है। मजदूरों और गरीबों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में कुछ नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में ठोस आर्थिक प्रावधानों के विपरीत सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे थे। मोदी की चरण वंदना में समर्पित इस बजट में छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की उपेक्षा और भेदभाव का कोई जिक्र नहीं था। पिछले बजट का ज्ञान फेल हो गया तो वित्त मंत्री इस बार लंगड़े बजट की गति लेकर आ गये। 15 सालों तक रमन सरकार मेट्रो ट्रेन का झुनझुना पकड़ाती थी, अब फिर से साय सरकार ने नये सिरे से राज्य की जनता को मेट्रो ट्रेन का झुनझुना पकड़ाया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि उद्योग नीति पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले वित्त मंत्री राज्य के वनोपजो पर आधारित उद्योगों, वनोपजो के वेल्यू एडिशन पर कुछ नहीं बोले। विश्वविद्यालयों की संख्या पर अपनी पीठ थपथपाने वाली साय सरकार ने अपने कार्यकाल में 1 भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोला।

प्रगति को गति देकर छत्तीसगढ़ को महाशक्ति बनाने वाला बजट : अमित चिमनानी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे पूर्ण बजट प्रस्ताव को विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने के प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का उद्घोष निरुपित किया है। श्री चिमनानी ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को क्रांतिकारी निर्णयों के जरिए जिस तीव्र गति से पूरा कर रही है और उसके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के प्रति गंभीरता से बजट में प्रावधान किए गए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश के विकास में और तीव्रता आएगी। श्री चिमनानी ने कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा सोमवार के विधानसभा में रखा गया बजट प्रस्ताव ऐतिहासिक है और यह केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की उन्नति की नई दिशा तय करने वाला प्रयास है।यह बजट प्रदेश की प्रगति को गति देकर छत्तीसगढ़ को महाशक्ति बनाने वाला बजट है। बजट में पंजीयन के 20 केंद्र मॉडल बनाने और हक़ त्याग शुल्क अब मात्र 500 रुपये में करने की घोषणा से आम जनता को काफी राहत दी जा रही है।

जितना बड़ा जनादेश, जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ीः अनुराग अग्रवाल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के दूसरे बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट में प्रदेश के सभी वर्ग जैसे किसान, महिला, युवा, छात्र, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा है । उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया था कि जब जनादेश बड़ा हो तो जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का पूर्ण प्रयास इस बजट में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश सरकार की आधारभूत संरचना के कार्यों के प्रति संजीदगी को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा यह बजट युवा वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला होगा हृङ्खस्नङ्ग जैसे विश्व स्तरीय संस्थान रायपुर में खुल रहे हैं। कुनकुरी में एक मेडिकल कॉलेज, 12 नर्सिंग कॉलेज, आठ फिजियोथैरेपी कॉलेज, तकनीकी विश्वविद्यालय का उन्नयन, शिक्षा के क्षेत्र में माइलस्टोन साबित होगा। हमने कहा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है।

नई आशाएं एवं विश्वास लेकर आने वाला है यह बजट : विकास मरकाम

रायपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सुशासन और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी प्रभावी लाभ प्रदान करने वाला है। यह बजट आदिवासियों के समावेशी विकास को लक्ष्य में रखकर जारी किया गया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, माताओं एवं बुजुर्गों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई है जिससे प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी के मन में न केवल उत्साह बढ़ेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास गाथा में आदिवासी समाज अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे सकेंगे। विकास मरकाम ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इनमें प्रमुख रूप से आदिवासी संस्कृति के लिए विशेष संग्रहालयों की स्थापना शामिल है, जिसके लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिला सुरक्षा पर बजट में कुछ नहींः वंदना राजपूत

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट आम जनता के अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक है। जो सिर्फ कागजों का ही शोभा बढ़ाता है धरातल पर बिल्कुल शून्य है। प्रदेश की महिलाओं को इस बजट से यह विश्वास था कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार पर कुछ विशेष पैकेज रहेगा लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं रहा ।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने पूछा कि पिछले बजट में 6 महिला पुलिस थाना खोलने की बात कही गई थी और यह सिर्फ बजट में था धरातल पर कुछ नहीं। पिछले बजट में भी बहुत सारे जनहित के लिए घोषणाएं किए गए थे उस बजट का जिसमें से 70 प्रतिशत तक की राशि भी खर्च नहीं कर पाए। जिसके कारण आज प्रदेश के जनता मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। इसमें ना युवाओं के रोजगार के संदर्भ में कोई रोडमैप है और ना ही महंगाई से निपटने कोई ठोस रणनीति। कॉलेज जाने वाले छात्रों से यात्रा भत्ता देने का वादा किया था।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

गति नहीं दुर्गति का दिशाहीन बजटः सुरेंद्र वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि आज प्रस्तुत साय सरकार के दुसरे बजट में पिछले वादों को भुला दिया गया है, न 1 लाख नई सरकारी नौकरी का ज़िक्र, न अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई रोड़मैप, न 500 में सिलेंडर याद रहा न, बेरोज़गारी भत्ता और न ही छात्रों को बस का फ्री पास। वित्तमंत्री टोपी चौधरी केवल तुकबंदी करते रहे, मोदी की पुरानी अधूरी गारंटीयों पर मौन रहकर केवल झूठा यशोगान करते रहे, दूसरी सरकारों के कार्यों और योजनाओं का श्रेय खुद ही ले लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार पूर्व में संचालित उद्योगों को भी संचालित करने में नाकाम रही है अब नए उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने का झूठा दावा कर रही है। हकीकत यह है कि पिछले 15 महीना के भीतर 300 से अधिक राइस मिल बंद हुए हैं, 450 से ज्यादा स्पंज आयरन और रोलिंग मिल की फैक्ट्रियां बंद हुई है, भाजपा सरकार की उपेक्षा के चलते ही 2-2 सरकारी शक्कर कारखाने प्रदेश में बंद हो गए, यह सरकार नौकरी देने नहीं बल्कि रोज़गार छीनने वाली सरकार है।

बजट छलावा एवं निराश करने वालाः शुक्ला

रायपुर। साय सरकार के दूसरे बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केवल ठगी और जुमलेबाजी के अलावा इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। महतारी वंदन योजना में लाखों की संख्या में पात्र हितग्राही योजना के लाभ से आज भी वंचित है लेकिन केवल 5500 करोड़ का बजट प्रावधान भाजपा सरकार के दुर्भावना का प्रमाण है। यदि सरकार की नियत सही होती और नए हितग्राहियों को शामिल करने की मंशा होती तो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कम से कम 10 हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया होता।प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि साय सरकार के वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि विगत एक साल में केवल 22 हजार लोगों को अयोध्या दर्शन करवा पाए हैं, इस रफ़्तार से 3 करोड़ आबादी को दर्शन करवाने में 1350 साल लगेंगे, वह भी तब जब जनसंख्या स्थिर हो जाए, सनातनियों को धोखा दे रही है साय सरकार। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि साय सरकार प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बार-बार झूठा श्रेय लेने का कुत्सित प्रयास कर रही है। 2011 के बाद से देश में आमजनगणना नहीं हुई है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगेः संजय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार को बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की घोषणा करके 46 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता मिलेगी। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां धान, दालें, तिलहन और अन्य खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन उत्पादों के उचित भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है, और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा 46 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ यह योजना छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वरदान साबित होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगा यह बजटः रोहरा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने इस बजट में न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए 5,326 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1800 करोड़, डॉ आंबेडकर अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के विस्तार के लिए 10 करोड़ और डॉ भीमराव आंबेडकर अस्पताल में उपकरणों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल बनाने की घोषणा करके प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधा से समृद्ध बनाने का काम कर रही है। श्री रोहरा ने कहा कि बजट 2025 में राज्य के युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं के विस्तार की घोषणा से राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को अपने हुनर को निखारने का बेहतर मंच उपलब्ध होगा। इसी दिशा में दुर्ग और सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की गई है। इन स्टेडियमों के निर्माण के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इन बहुउद्देशीय स्टेडियमों में विभिन्न खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर : शालिनी राजपूत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। नारी शक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार ने इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है। श्रीमती राजपूत ने प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा का स्वागत करके कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग विभाग में नया आईवीएफ सेंटर बनाने की घोषणा करके प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपने संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। श्रीमती राजपूत ने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को विशेष रूप से समर्थन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ बजट 2025-26

समावेशी विकास को गति देने वाला बजट : डिप्टी सीएम विजय शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट अटल निर्माण वर्ष के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को गति (गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ) के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए 40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए 44 करोड़ का बजट रखा गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए 25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए।

हमने बनाया है हम ही संवारेंगे ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने वाला सर्व समावेशी बजट : केदार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के वनमंत्री केदार कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा इस बजट को भाजपा के ध्येय वाक्य हमने बनाया है हम ही संवारेंगे को चरितार्थ करने वाला बजट बताया है।

मंत्री केदार कश्यप ने बजट 2025 को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस कल्पना और विचार को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए साय सरकार विकास के पथ पर अब दौड़ने लगी है। आज का बजट बताता है कि हमने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के कालातीत काल से निकाल कर आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

कांग्रेस सरकार में बस्तर विकास के मार्ग से भटक गई थी। बस्तर भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। ऐसे सुदूर बस्तर के लिए इस बजट में करोड़ों का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हमने ही बनाया है और हम ही संवार रहे हैं।

वनमंत्री केदार कश्यप ने बजट को लेकर कहा कि बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बस्तर फाइटर्स का कार्य सराहनीय रहा है। और इस बात को ध्यान में रख विष्णुदेव साय सरकार ने 3200 अतिरिक्त फाइटर्स के पदों का सृजन का प्रावधान इस बजट में किया है। जिससे बस्तर के युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.